RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ... सच

माही की गूंज

प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-02, अंक - 35 (साप्ताहिक) खवासा, गुरुवार 04 जून 2020 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

इंडिया का नाम बदलकर भारत करने वाली याचिका में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इंकार

नईदिल्ली, एजेंसी। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में इंडिया की जगह भारत नाम रखने के लिए संविधान में संशोधन की याचिका में दखल से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि संबंधित अथॉरिटी प्रतिवेदन की तरह देखेगी इसके लिए संबंधित मंत्रालय के सामने याचिका भेजी जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इसके लिए सरकार के सामने ही मांग रखे। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एसए बोबडे की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में कहा कि याचिकाकर्ता ने इस मामले में कोर्ट को क्यों अप्रोच किया है जबकि संविधान में साफ लिखा है कि इंडिया जो कि भारत है। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि इंडिया ग्रीक शब्द इंडिका से आया है और इस नाम को हटाया जाना चाहिए। जब याचिकाकर्ता ने लगातार ये दलील रखी और सुप्रीम कोर्ट का रुख याचिका सुनने के लिए नहीं दिखा तो याचिकाकर्ता ने कहा कि इस याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर संबंधित मंत्रालय के सामने भेजने की इजाजत दी जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि संविधान में भी भारत नाम लिखा है। लिखा है इंडिया दैट इज भारत। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप संबंधित मंत्रालय के सामने अपना प्रतिवेदन दें और सरकार को संतुष्ट करें।

सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह संविधान में बदलाव करे और इंडिया शब्द को बदलकर हिंदुस्तान या फिर भारत कर दे। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर दो जून को सुनवाई करने का फैसला किया था। याचिकाकर्ता ने कहा है कि हमारी राष्ट्रीयता के लिए भारत शब्द को संविधान में जोड़ना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से मना करते हुए याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर संबंधित मंत्रालय के सामने भेजने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद-1 में बदलाव किया जाए। इस अनुच्छेद के तहत नाम है। इसमें भारत या हिंदुस्तान दर्ज होना चाहिए। याचिका में कहा गया था कि अनुच्छेद-1 में इंडिया का इस्तेमाल है। ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद इस इंग्लिश नाम को बदलकर भारत नाम दर्ज होना चाहिए। भारत की पहचान सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद-1 में बदलाव होना चाहिए और भारत नाम वहां दर्ज होना चाहिए और इंडिया नाम हटाया जाना चाहिए।

डोकलाम विवाद की तरह दोनों देशों के बीच वार्ता से ही निकलेगा हल: राजनाथ

नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माना है कि लद्दाख में गलवान वैली और पैंगोग त्सो के चार पाइंट्स पर भारत-चीन के सैनिक डटे हुए हैं। हालांकि इस बीच तनाव बढ़ाने वाली कोई नई घटना नहीं हुई है लेकिन फिर भी तनाव बरकरार है। रक्षामंत्री ने उम्मीद जताई कि 6 जून को फिर दोनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर होने वाली बातचीत में विवाद का कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा।

उन्होंने कहा कि अब तक कई दौर की वार्ता में दोनों देशों के सैन्य अधिकारी किसी ऐसे नतीजे तक नहीं पहुंच पाए हैं जिससे समाधान निकल सके। इसलिए साथ-साथ भारत-चीन के बीच कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत जारी है।

लेह स्थित 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह अगले दौर की बातचीत का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। इस बार चीनी कर्नल, ब्रिगेडियर और प्रमुख जनरलों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि वार्ता से समस्या का हल निकलना चाहिए क्योंकि इससे पहले कई दौर की बातचीत लंबे सैन्य गतिरोध को तोड़ने में विफल रही है। वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारी चीनी सैन्य निर्माण को लेकर चल रहे तनाव के बीच दोनों देशों की सेनाओं ने संकट को हल करने के लिए मंगलवार को भी बातचीत की लेकिन यह वार्ता भी पिछली बैठकों की तरह बेनतीजा रही।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे पहले भी डोकलाम विवाद का हल दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच वार्ता से कूटनीतिक स्तर पर निकला है। पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन की सेनाओं के बीच लगभग एक महीने से चल रहे गतिरोध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चीनी सैनिक एक श्वड्डी संख्याश् उन क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गए हैं जिस पर चीन का दावा है कि यह उसका क्षेत्र है। चीन के बाद वहां भारत की तरफसे भी ज्यादा सैनिकों की तैनाती की गई है और भारत ने भी स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि अब तक सैन्य अधिकारियों के बीच वार्ताओं में समस्या का हल नहीं निकल पाया है लेकिन वार्ता के रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। रक्षामंत्री ने उम्मीद जताई कि 6 जून को फिर दोनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर होने वाली बातचीत में विवाद का कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा।

चीनी सैनिकों की भारतीय सीमा में घुसपैठ पर स्थिति स्पष्ट करें सरकार : राहुल गांधी

नई दिल्ली, एजेंसी। लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिकों के जमावड़े की खबरों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कथित घुसपैठ पर बुधवार को सवाल उठाया कि क्या सरकार इसकी पुष्टि कर सकती है कि चीन का कोई सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल नहीं हुआ? उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, 'क्या भारत सरकार इसकी पुष्टि कर सकती है कि चीन का कोई सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल नहीं हुआ?' गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर लगभग एक महीने से चले आ रहे गतिरोध के संदर्भ में बुधवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिक 'अच्छी खासी संख्या में' आ गए हैं और भारत ने भी स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। सिंह ने कहा कि भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच छह जून को बैठक निर्धारित है। इसके साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि भारत अपनी स्थिति से पीछे नहीं हटेगा। खबरों के अनुसार, एलएसी पर भारत की तरफगलवान घाटी और पैंगोंग त्सो क्षेत्र में चीनी सैनिक अच्छी-खासी संख्या में डेरा डाले हुए हैं।

पुलवामा मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकी ढेर, हथियार व गोला-बारूद बरामद

पुलवामा, एजेंसी। पुलवामा जिले के कंगन क्षेत्र में बुधवार सुबह आतंकियों तथा सुरक्षाबलों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने तीन आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के शवों के साथ भारी मात्रा में हथियार व गोला-बारूद बरामद हुआ है। क्षेत्र में सुरक्षाबलों द्वारा फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। मारे गए सभी आतंकी जैश-ए-मोहम्मद संगठन से संबंधित हैं। फिलहाल इन आतंकियों की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं मुठभेड़ के दौरान हिंसक प्रदर्शनों की आशंका के चलते प्रशासन ने जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है।

जानकारी के अनुसार बुधवार तड़के जिले के कंगन के अंतर्गत अस्तान मोहल्ला में आतंकियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही सेना की 55 आरआर, सीआरपीएफ 183 बटालियन तथा एसओजी की एक संयुक्त टीम ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी अभियान के दौरान क्षेत्र में छिपे आतंकियों ने सुरक्षाबलों को पास आते देख गोलीबारी की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों तीनों आतंकियों को मार गिराया है। क्षेत्र में फिलहाल अन्य आतंकियों की संभावना के चलते तलाशी अभियान जारी है।

वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी पुलवामा मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए कहा कि जैश-ए-मोहम्मद के तीनों आतंकी मार गिराए गए हैं, जबकि इस दौरान हथियार तथा गोला-बारूद भी बरामद किया गया है।

8 जून से शुरू होगी चारधाम यात्रा, सीमित श्रद्धालुओं को मिलेगी अनुमति

रूद्र प्रयाग, एजेंसी। लॉकडाउन 5.0 में धार्मिक स्थलों को खोलने की मिली इजाजत के बाद उत्तराखंड सरकार राज्य में पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को शुरू करने की तैयारी में है। अब प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा शुरू करने की तैयारी में जुट गई है। 8 जून के बाद सरकार सीमित संख्या में चारधाम यात्रा को शुरू करेगी। हालांकि शुरुआत में केवल राज्य के लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी। दूसरे दौर में अन्य राज्यों से बात कर बाहरी यात्रियों के लिए यात्रा को शुरू किया जाएगा। जारी बयान के मुताबिक चारधाम यात्रा को शुरू किया जाएगा। मगर यात्रा की शुरुआत सीमित संख्या से होगी। दूसरे राज्यों से बसों के संचालन की अनुमति मिलने के बाद चारधाम यात्रा को दूसरे राज्यों के पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के लिए खोला जाएगा।दूसरे राज्यों की आपसी सहमति के बाद ही बसों के संचालन का फैसला लिया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश के प्रसिद्ध धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बदरीनाथ के कपाट खुलने के बाद ही यात्रा का संचालन पूरी तरह से बंद है। बता दें कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट एक लंबे शीतावकाश के बाद 15 मई को तड़के खोल दिए गए थे। लेकिन लॉकडाउन के चलते इस मौके पर बदरीनाथ में कोई मौजूद नहीं रहा। महज गिनती के ही लोग मंदिर में दिखे। जबकि पिछले साल कपाट खुलने के बाद पहले दिल लगभग 10,000 श्रद्धालुओं ने मंदिर के दर्शन किए थे।

ट्रम्प ने मोदी को जी7 शिखरवार्ता में भाग लेने का दिया निमंत्रण

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प से भारत-चीन सीमा की मौजूदा स्थिति तथा जी7 समूह में भारत को शामिल किए जाने सहित विभिन्न मुद्दों पर मंगलवार को टेलीफोन पर बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोदी को जी7 समूह की अगली शिखरवार्ता में भाग लेने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार मोदी ने दुनिया के प्रमुख देशों के संगठन जी7 की शिखरवार्ता में भारत को शामिल किए जाने के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प की पहल का स्वागत किया। ट्रम्प ने प्रधानमंत्री को बताया था कि जी7 समूह की अध्यक्षता संभाल रहा अमेरिका इस मंच का विस्तार करने का इच्छुक है। समूह के मौजूदा 7 सदस्यों के अलावा भारत सहित कुछ प्रमुख देशों को इसमें शामिल किया जाएगा। मोदी ने राष्ट्रपति ट्रम्प की इस पहल को सकारात्मक और दूरदर्शी बताते हुए कहा कि यह 'कोविड-19 पश्चात विश्व की हकीकत के अनुरूप ही है। मोदी ने कहा कि भारत अमेरिका और जी7 देशों की शिखर-वार्ता को सफल बनाने के लिए अमेरिका और अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने में खुशी महसूस करेगा।

राज्यसभा की रेस में पिछड़ रहे हैं दिग्विजय सिंह? कांग्रेस के खाते में जाएगी 1 सीट, उम्मीदवार हैं 2

उपचुनाव की वजह से असमंजस में कांग्रेस, राज्यसभा किसे भेजे

दलित कार्ड के कारण राज्यसभा की रेस में पिछड़ सकते हैं दिग्विजय सिंह

भोपाल, एजेंसी। एमपी से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 19 जून को वोटिंग होगी। कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। वहीं, कांग्रेस ने भी 2 उम्मीदवार उतारे। दिग्विजय सिंह प्राथमिक सीट से हैं, तो उनकी जीत अभी तक पक्की मानी जा रही है। लेकिन बदले सियासी हालात में अब उन्हें लेकर संशय बरकरार है। पार्टी उपचुनाव को देखते हुए एमपी में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। साथ ही पार्टी के अंदर से ही यह आवाज उठ रही है कि फुल सिंह बरैया को राज्यसभा भेजा जाए।

दर असल, कांग्रेस की तरफसे राज्यसभा के लिए जब 2 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया था, तब प्रदेश में सरकार थी। उस वक्त तक यह तय था कि कांग्रेस 2 सीटें निकाल सकती हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोडऩे के बाद कांग्रेस के 22 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया। उसके बाद सियासी समीकरण बदल गए हैं। अभी के हालात में 2 सीट पर बीजेपी की जीत पक्की है। वहीं, राज्यसभा चुनाव के बाद एमपी में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 24 में से 16 सीट ग्वालियर-चंबल संभाग में हैं।

पिछड़ सकते हैं दिग्गी

कांग्रेस के हाथ से सत्ता जाने के बाद चुनावों के समीकरण बदल गया है। चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही दलित चेहरे को राज्यसभा में भेजने की मांग उठने लगी है। साथ ही दिग्गी विरोधी खेमा यह मांग करने लगे हैं कि बरैया को राज्यसभा भेज बीजेपी का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। बरैया के पक्ष में लॉबिंग कर रहे नेताओं का तर्क है कि उन्हें राज्यसभा भेज में आरक्षित वर्ग के वोटों का लाभ ले सकते हैं। अगर पार्टी इस पर राजी हो गई तो दिग्विजय सिंह राज्यसभा नहीं पहुंच पाएंगे।

आरक्षित वर्ग के वोट की रणनीति

ग्वालियर-चंबल इलाके में आरक्षित वर्गों का वोट काफी है। बरैया समर्थकों के तर्क पर दिग्गी खेमा ने भी जवाब दिया है। दिग्विजय सिंह के लोगों का कहना है कि राज्यसभा इन्हें ही भेजा जाए। फुल सिंह बरैया को उपचुनाव में पार्टी किसी सीट से उम्मीदवार बनाए। इससे भी आरक्षित वर्ग के वोट पार्टी के पक्ष में आएंगे। वहीं, मीडिया से बात करते हुए फुल सिंह बरैया ने कहा कि जब तक निर्वाचन नहीं हो जाता तब तक वे मुकाबले में हैं। कांग्रेस ने मुझे उम्मीदवार बनाया है।

बदल गया है समीकरण

दरअसल, एमपी में 23 मार्च तक कांग्रेस की सरकार थी। सिंधिया समर्थकों के इस्तीफे के बाद कमलनाथ की सरकार चली गई। सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों को मिलाकर कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या 121 थी। वहीं, बीजेपी के पास 107 विधायक थे। तत्कालीन समीकरण के हिसाब से कांग्रेस को राज्यसभा की 2 सीटें मिल रही थीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी से इस्तीफा देकर समीकरण बदल दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस 1 ही सीट जीत सकती है। बदले हालत में पार्टी को ही तय करना है कि राज्यसभा कौन जाएगा।

माफ कीजिए साहब! काम काबिले तारीफ तो नहीं, कर्तव्य है आपका

माही की गूंज, झाबुआ। मुज़म्मील मंसूरी

अपने कर्तव्यों की पूर्ण परायणता अच्छी बात होती है। होना भी चाहिए, क्योंकि आपको सौंपी गई जिम्मेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों में आशाएं है आपके प्रति। लोग निश्चिंत हो जाते है आपकी उपस्थिति और आपके लिए गए कर्तव्य परायणता के संकल्प को देख व सुनकर। मगर जब आप अपने कर्तव्य को किसी लालच या लालसा के लिए पूरा करते हो या अपने कर्तव्यों की तारीफ सुनना चाहते है, तो यह आपकी कामयाबी तो नहीं है। आपकी कर्तव्यों के प्रति निष्ठा इतनी होना चाहिए कि आपको किसी कामयाबी का ढिंढोरा ना पीटना पड़े, बल्कि लोग खुद आपकी कामयाबी के गुणगान खुद ही करने लगे। इसे ही असर कामयाबी भी कहा जात है।

इन दिनों जिले में भी कुछ एक घटनाक्रम ऐसा हुआ। एक साहब जिन पर पूरे जिले की सुरक्षा का जिम्मा है, ने अपने कर्तव्यों की परायणता को कामयाबी के रूप में प्रसारित करने का तथाकथित असरकारी तरीके से प्रयास किया। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच यह लग रहा था कि जिले में पुलिस विभाग को ठीक से सुर्खियों में बने रहने की जगह नहीं मिल रही है। तो साहब ने भी एक पासा ऐसा फैंका कि अपने कर्तव्यों को कामयाबी बताकर सुर्खियां बटोरने लगे। साहब चाहते तो यह काम विभागीय स्तर पर भी कर सकते थे, लेकिन इस काम के लिए उन्होंने चुना अपने एक करीबी पत्रकार मित्र को। वो कहते है तोता जिसका होता है तारीफभी उसी की करता है। तो तोते ने अपना काम शुरू किया और जिले में चल रहे कई अखबारों को साहब की तथाकथित कामयाबी का एक समाचार आंकड़ों सहित बनाकर प्रकाशित करने हेतु भेजा। कई अखबारों ने इसे प्रकाशित किया और कइयों ने इसमें चापलूसी की बू ढूंढ़ ली और डाल दिया कचरे के डब्बे में। जिले का इतिहास रहा है कि जिले को जितने भी कप्तान मिले लगभग सभी ने विभागीय स्तर पर प्रेसनोट जारी कर दैनिक जानकारियां व आपराधिक रिकार्डों में सफलता और विफलता की जानकारियां उपलब्ध कराई है। वर्तमान स्थिति में साहब या विभागीय स्तर पर इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया। मतलब सीधा-सीधा, मीडिया से दूरी। हां कभी कभार महीने- दो महीने में कुछ तोतो को बुलाकर चाय-नाश्ता जरूर करवाया जाता। ताकि वह साहब को मियां मिट्ठू बनाए रखे। यह तो पक्का है कि महीने दो महीने में होने वाली इन चाय-नाश्ता मीटिंगों में कोई पत्रकार तो शामिल नहीं होता। यह दूरी कब तक जारी रहेगी इसका कोई अंदाजा नहीं? क्योंकि साहब को पत्रकारों की नहीं तोतों की जरूरत है। ठीक है साहब तोतों आपको मुबारक।

मगर हम तो पत्रकार है, अच्छे-बुरे सब पर हमारी नजर है, तोतों की तरह हमने कोई रट्टा नहीं मारा, जो दिखता है वही लिखते है। सच्चई की तह तक जाने की कोशिश करते है। साहब की जिन उपलब्धियों को उनके तोते ने गिनाया है उसकी जमीनी हकीकत विपरीत ही है।

जारी किए गए समाचार में पुलिस की सजगता से अपराधों के ग्राफमें गिरावट आने का दावा किया गया है। विभाग में दौड़ रहे कागजी घोड़ों के आधार पर तोते ने वर्ष 2018 से 2019 के बीच एक साल में 29.17 प्रतिशत की अपराधों में गिरावट बताई। पिछले पांच महीनें में आपराधिक आंकड़े में भी 5.16 प्रतिशत की गिरावट बताई। इस आंकड़े की हकीकत तो यह है कि पिछले दो माह से जिले में लॉकडाउन है और इस अवधी में बेशक अपराधिक रिकार्ड में जबरदस्त गिरावट आई है। समाचार के अनुसार जो अपराधों का ग्राफ बताया गया उसमें आपराधिक रिकॉर्ड में वर्ष 2017 में 4000, 2018 में 3211, 2019 में 2257 और 2020 में मई तक 791 मामले दर्शाए गए।

उस यह दावा किया कि सबसे ज्यादा असर एसपी के द्वारा अपने स्तर पर तैयार करवाई गई महिला जागरूकता तथा सुरक्षा अभियान पर केंद्रित शॉर्ट फिल्म भूल एक नसीहत का सार्वजनिक स्थानों के साथ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रदर्शन करवाया गया। जिससे स्कूल व कॉलेज की छात्राओं के साथ छात्रों में भी जागरूकता आई। मतलब अपराधों के ग्राफको कम करने में इस फिल्म की अहम भूमिका रही। अब सवाल यह कि कोई अपराधी किस तरह कोई फिल्म देखकर अपराध करना बंद कर सकता है। और अगर ऐसा है तो फिर बॉलीवुड ने तो ऐसी कई प्रेरणादायक फिल्में बनाई है। इन फिल्मों का देश भर के सिनेमाघरों में प्रदर्शन भी हुआ है। मगर इस तरह के अपराधों के ग्राफमें गिरावट देश में क्यों दर्ज नहीं हो पाई। यह अजूबा इस जिले में क्यों और कैसे हो गया। ऐसा भी नहीं है कि जिलेवासियें ने सिर्फसाहब की दिखाई फिल्म ही देखी हो। इस आदिवासी जिले में सिनेमाघर हमेशा, हर शो में फूल ही मिलेंगे। तो फिर प्रेरणा साहब द्वारा दिखाई गई फिल्मों से कैसे मिल गई। खैर छोड़िए! सवाल तो यह भी उठता है कि जारी किए गए आंकड़ों में साहब या उनके विभाग को सफलता कितनी मिली?

जिले की वर्तमान स्थिति पर बात करें तो साहब के दावें आपको सिर्फखोखले दिखाई देंगे और उनके तोते की आवाज ज्यादा मधुर सुनाई देगी। जिले में लॉकडाउन के दौरान अपराधों का ग्राफ कम रहा, बावजूद उसके दिन दहाड़े लूट जैसी घटनाएं हुई और अपराधियों का अब तक पुलिस के हत्थे न लगना, चोरियों का सिलसिला जिले में अब भी बदस्तूर जारी है। हद तो तब हो जाती है जब लॉकडाउन के दौरान ट्राले जैसा वाहन चोरी हो जाता है जबकि शहर की सीमाएं सील है। आपसी विवाद में ही सही लेकिन पुलिस के इस मुस्तैदी वाले दौर में कत्ल तक हो रहे है। साहब का यह दावा उस वक्त और भी झूठा लगता है जब आप ही के विभाग के जवानों का वीडियों इंसाफ की बात करने बजाय भांजगड़ी व शराब का सेवन करते हुए वायरल हो जाता है। अखबारों की सुर्खियां भी बनता है। ऐसे कई मामले है जो ऊंगलियों पर गिनाए जा सकते है। लेकिन साहब का विभाग कागजी घोड़ों पर सवार है और साहब के तोते उन्हें मियां मिट्ठू बनाने में लगे हुए है।

जिम खोलने की अनुमति को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौपा कलेक्टर को ज्ञापन

कलेक्टर कार्यालय में पहुचे जिम संचालक।

माही की गूंज, झाबुआ।

विगत दो माह से नगर में लॉकडाउन के चलते जिम खोलने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर प्रबल सिपाहा को ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें ज्ञापन में बताया गया कि जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले की समस्त जिम व्यायाम शालाएं भी बंद हो कर व्यायामशाला संचालक बेरोजगार हो चुके है। यह ि कइस दौरान संचालको का व्यायम स्थल, दुकानो का जजारो रूपये का किराया बकया है। मकान, मालिक द्वार किराए के लिये दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही ऋण लेकर खरीदी गई जिम की सामग्रीयां की किश्ते भी नही भर पा रहे है। यही की उक्त अवधि मे बमुश्किल हमारा जीवन यापन हुआ हैं वही हजारों रूपये का कर्ज भी हो चुका है। ज्ञापन मे जिम संचालको के द्वारा इस कर्ज से मुक्ति हेतु सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाने की मांग की है। वही जिम संचालको के द्वारा यह विश्वास दिलाया गया कि वह भी जिला प्रशासन के नियमो का पालन करते हुये जिमे को सेनेटाईजर कर , सोश्यल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये आने जाने वाले लोगो के हाथ भी सेनेटाईहर कर मुह पर मास्क लगाने के बाद ही प्रवेश देंगे। जिम संचालको द्वारा ज्ञापन मे यह भी कहा गया कि जिम खोलने की छूट प्रदाय कि जाये जिससे की इस महामारी में योगा व व्यायाम कर रोग प्रतिरोधक क्षमता को अधिक से अधिक लोगो की बढाई जा सके।

वर्ष 2017 में लिखी गई ग्राम पंचायत असालिया में भ्रष्टाचार की नई इबारत

जांच में सिद्ध हुए भ्रष्टाचार तक को रिश्वत की आड़ में निगल गए अधिकारी

माही की गूंज, पेटलावद।

पेटलावद विकास खंड की ग्राम पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार के खेल को हम सतत उजागर मय प्रमाण कर रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड में फर्जी बिलों का भुगतान और धरातल पर गायब रोड़। ग्राम पंचायत और उसके किए भ्रष्टाचार को चीख-चीख कर बता रही हैं। शिकायतकर्ताओं और ग्रामीणों के दिखावे के लिए अधिकारियों द्वारा पंचायत के दौरे और जांच में भ्रष्टाचार होने के प्रतिवेदन तक तैयार किए जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद की कार्यवाही नोटों के बंडल के नीचे ऐसी दबी कि ईमानदारी की कोई कलम उस पर नहीं चल सकी। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारने वाले हमारी कलम से आपके कोने कारनामें जनता तक और जनता के माध्यम ने न्यायालय तक पहुंचा कर एक न एक दिन न्याय जरूर लेंगे। कहते हैं सत्य परेशान हो सकता हैं, लेकिन पराजित नहीं। उसी सत्य के लिए गूंज की कलम सतत चलती रहेगी।

ग्राम पंचायत असालिया में वर्ष 2017 में लिखी गई भ्रष्टाचार की एक ऐसी इबारत जिसके गवाह तहसील और जिले के जवाबदार अधिकारी बन चुके है। लेकिन जांच और कार्यवाही के नाम पर केवल वसूली की गई। यहां ग्राम पंचायत असालिया के बेडाखो फलिये में तेजाजी मंदिर से रूपजी के घर तक का 6 लाख का सीसी रोड़, ग्राम असालिया का ग्राम पंचायत से तेरसिंह के घर तक का सीसी रोड लागत 10.80 लाख, ग्राम असालिया का रमेश बारिया के घर से मुक्ति धाम तक का सीसी रोड लागत 4.80 लाख के कुल तीन रोड लागत लगभग 23 लाख रुपए धरातल से गायब होकर इन तीनों स्थानों पर एक गेती तक नही चली हैं। वहीं ग्राम असालिया का ही मिडिल स्कूल से पांगला निनामा के घर तक का सीसी रोड लागत 10 लाख 30 हजार का रोड़ अधूरा बनाया गया है। सभी रोडों की वर्ष 2017 में स्वीकृत हुए थे और शासन द्वारा दी गई राशि ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव और सहायक सचिव ने अलग-अलग एजेंसी के फर्जी बिल लगा कर निकाल ली। ग्राम पंचायत के ग्रामीण पिछले दो साल से मुख्यमंत्री ऑनलाइन ,181 से जनसुनवाई और जनपद स्तर पर लिखित शिकायत कर चुके है, लेकिन अधिकारी अपनी रिश्वत का पेट इतना बड़ा हो गया हैं कि कोई भ्रष्टाचार सिद्ध होने के बाद भी दिखाई नहीं देता हैं।

ग्राम पंचायत के ग्रामीण अमरसिंह निनामा, धारजी मुनिया, कालु मुनिया आदि ने बताया कि रोड़ के लिए हम पिछले तीन वर्षो से परेशान हो रहे हैंव बारिश में यहां से निकल पाना भी दूभर हैं। बीमार-बुजुर्ग आदि को खाट पर डाल कर मुख्य मार्ग तक लाना पड़ता हैं। ग्राम पंचायत पूरा पैसा निकाल कर खा गई। अब हम अब भी परेशानी में घिरे हुवे हैं।

नहीं हुई कार्यवाही तो जाएंगे न्यायालय

पंचायत के भ्रष्टाचार को अब चुनौती देने के लिए गांव के पढ़े-लिखे युवा जागृत हो गए है। इनका कहना है कि अब अगर की कार्यवाही नहीं हुई तो हम न्यायालय की भी शरण में जाएंगे। भ्रष्ट अधिकारियों को भी न्यायालय में घसीटेंगे। गांव के शिक्षत युवा विककी गामड़ ने कहा है कि हम जल्द ही विधिक सहायता लेकर ग्राम पंचायत और अधिकारियों से न्यायालय में ही जवाब मांगेंगे कि आखिर क्यों सबूतों के बाद भी कोई कार्यवाही और एफआईआर दर्ज नहीं की गई।

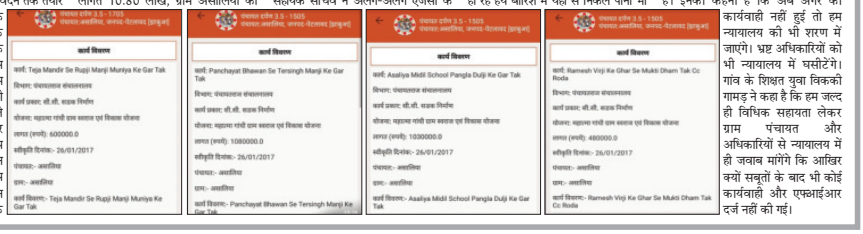

बिना अनुमति खोद लिया जेसीबी से मोर्रम

ग्रामीणों का आरोप पौधों के लिए खोदे गए कंटूर भी भर दिए

इस तरह मशीन के द्वारा खोदा जा रहा मोर्रम।

मशीन से खोदकर इस तरह खेत में बिछाया गया।

माही की गूंज ,पेटलावद।

ग्राम पंचायत बरवेट के जुलवानिया फलिये में बने शमशान की भूमि से गांव के ही शिक्षक ने अपने खेत में भराव करने के लिए जेसीबी के माध्यम में 150-200 ट्रिप मोहर्रम खोद के अपने खेत में डाल दिया। ग्रामीणों का आरोप हैं कि यहां से बड़ी मात्रा में खोदा गए मोहर्रम के लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली है। फलिये के विनोद और मानसिंह का कहना है कि ग्राम पंचायत ने यहां तीन हो पौधा रोपड़ कार्य हेतु कंटूर खोदने का कार्य मजदूरों से करवाया था। जिसमें से अभी एक हफ्ते की ही मजदूरी भुगतान हुआ हैं और शासन के पैसे लगा कर खोदे गए बहुत सारे कन्टूर जेसीबी और ट्रेक्टर चलने के दौरान भर दिए। लेकिन ग्राम पंचायत ने इसकी सूध नहीं ली। ग्रामीण विनोद का आरोप हैं कि ग्राम पंचायत पहले भी मुक्तिधाम की भूमि पर अशोक वाटिका के नाम पर शासन से लाखों ऐंठ चुकी है, लेकिन यहां एक पौधा जीवित नहीं हैं। अभी फिर शासन के पैसे बर्बाद कर दिए गए। ग्राम पंचायत के सचिव कैलाश भाभर का कहना है कि मोहर्रम खोदने के लिए ग्राम पंचायत से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई और यदि राजस्व विभाग ने कोई अनुमति हुई हो तो न राजस्व की ओर से न ही मोहर्रम खोदने वाले की ओर से कोई सूचना ग्राम पंचायत को दी गई है। कंटूर भरे जाने के ग्रामीणों के आरोप पर सचिव का कहना है कि जहां से मोहर्रम खोदा गया हैं। उसकी दूसरी और कन्टूर खोदे गए है। भारी मात्रा में मोहर्रम खोदा गया ये तो सही हैं। हमारे द्वारा ली गई जानकारी से भी पता चला है कि राजस्व विभाग की ओर से ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई। ग्रामीणों के आरोपो में कितनी सच्चाई हैं वो तो अधिकारी की जांच के बाद ही पता चल सकेगा।

पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पकड़ी लाखों रूपए की अवैध शराब

माही की गूंज, झाबुआ। बीती रात रणापुर पुलिस ने मुखबिर की सुचना पर काफी जद्दोजहद के बाद रणापुर से महज 7 किलो मीटर दूर ग्रामी ढाकनीतलाई मे अवैध शराब से भरी आईसर पकड़ी। जिसमें लगभग 200 पेटी मांटंट बियर के डिब्बे के पेटिया बताई जा रही है। पूरे घटनाक्रम मं पुलिस पर प्रकरण दर्ज नहीं करने का दबाव बनाया गया। लेकिन देर रात सत्तापक्ष के दबाव में पुलिस को कार्यवाही करनी पड़ी। शराब का आरोपी फरार बताया जा रहा है।

सुबह 8 से शाम 6 बजे तक खुली रहेगी नगर की दुकानें

लॉकडाउन 5.0 की नई गाईडलाइन आने पर नगरवासियों को मिली एक और राहत

माही की गूंज, झाबुआ।

लॉकडाउन को लेकर जिले कलेक्टर प्रबल सिपाह ने नई गाईड लाईन जारी की है जिसमें लॉकडाउन 5.0 की नगई गाईड लाइन्स की तरह होगी लॉकडाउन के पाचवें चरण को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए है। जिसमे लॉकडाउन मे पूर्व की तरह से लॉकडाउन की सभी नियम रहेंगे। आशिक छूट के बाद दुकान संचालकों के खुलने एवं बंद करने के समय मे परिवर्तन किया गया है। जिसमें उन्हे सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई है। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नगर में आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। पान , गुटका, तंबाकू, दुकाने, हाटेल-हलवाई, रेस्टॉरेन्ट, चाय-केटिंग,चाट मसाले, सिनेमाघर, टूरिज्म पिकनिक स्पॉट, स्विमिग पूल, शॉपिंग मॉल, सार्वजनिक पार्क, पुस्तकालय, जिम, खेल कूद गतिविधियां, स्टेडियम , मैरिज गार्डन बंद रहेंगे। शहरी एवं साप्ताहिक हाट बाजार पूर्व की तरह की बंद रहेंगे। शैक्षणिक संस्थान स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी केन्द्र बंद रहेंगे। वहीं पूर्व की तरह की बसों तथा आवामन के साधनों जिसमें ऑटो भी आगामी आदेश तक यथावत बंद रहेंगे।

नगर में आंशिक छूट के साथ सटोरियों ने भी खोला अपना धंधा

युवा वर्ग धंस रहा सट्टे के दलदल में

माही की गूंज, झाबुआ। कोरोना वायरस के सक्रमण की चौन को रोकने के लिए झाबुआ नगर सहित पूरे जिले को लॉकडाउन किया गया था । जिस पर से प्रशासन की आंशिक छूट के बाद से ही सटोरियो ने भी अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया। जिला पुलिस अधीक्षक विनित जैन के अनुसार जिले भर मे सटौरियो को सफाया करना है बताया गया था लेकिन आज भी जिला तो ठिक नगर में ही सटौरिया खुले आम घूम रहे है। वहीं कुछ एक दो सटौरियो को पकड़कर पुलिस के द्वारा कागजी कार्यवाही पूर्ण की जा रही है। नगर मे लॉकडाउन के तहत मिली आंशिक छूट के दौरान सटौरियो ने अपने कारोबार शुरू कर दिए है। वहीं भी गलियों कुचौ मै घूम घूम कर ये सटौरिये अपने सट्टे का कारोबार कर रहे है। इन सटौरियो ने अपना कोई एक ठिकाना नही बना रखा है ये पुरे नगर मे घूमते फिरते ही सट्टे का नबर लगाकर खायिवाल बन अपना काम कर रहे है।

नगर में इन सटौरिये के कारण युवा लाबी इस दलदल की ओर धसती जा रही है। वही इन सटौरियो के कारण नगर में युवा वर्ग को शामिल कर इनसे सट्टे का कारोबार कर उन्हे लूटा जा रहा है। वही ऐसे कई युवा वर्ग इस गौरख धंधे मे फंस चुके है जिनमें कई युवा वर्ग को सट्टे के पैसे जुटाने ओर उसे खेलने के लिये अपराध का सहारा लेना पड़ता है। जिसमे उनके द्वारा कई ऐसे कृत्य किये जा रहे है जो समाज एवं कानून के लिये घातक सिद्ध हो रहे है। पूर्व मे भी नगर में कई युवा वर्ग के द्वारा ही बड़े-बड़े कुक्रत्य किये जा चुके है। जिससे पुरा नगर हिल चुका है। वही दूसरी ओर आज भी युवा वर्ग इस दलदल की ओर झुकता जा रहा है जिससे की पुरी युवा पीढ़ी का भविष्य अधकार की ओर बढ़ रहा है। ऐसे मे नवयुवको का भविष्य के साथ उनके पूरे परिवार का भविष्य खतरे से घीरा हुआ है। नगर में पुलिस की मुस्तैदी का होने लगी है। जिससे की इन सटौरियो के हौसले धीरे धीरे फिर से बुलंद होते जा रहे है। ऐसे में यदि इन सटौरियो पर लगाम नही कसी जाये तो ये पुरे नगर को एक सट्टे का दलदल बना देंगे। जिला पुलिस प्रशासन को इस ध्यान देने की दरकार है।

आपदा में भी कमाई का अवसर ढूंढ ही लिया ग्राम पंचायत बामनिया ने

माही की गूंज, बामनिया। गौरव भंडारी

भ्रष्टाचार के लिए जिले की सबसे बदनाम ग्राम पंचायत बामनिया, जो बाजार बैठक वसूली से शौचालय निर्माण कार्य की राशि वितरण करने तक में भ्रष्टचार करने वाली है। उसने आपदा में भी कमाई का अवसर ढूंढ लिया है। बामनिया पंचायत के कारिंदों ने कोरोना जैसी महामारी के समय जबकि पूरा देश गत दो माह से लॉक डाउन से गुजर रहा है और कई परिवार आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में बामनिया पंचायत के स्वयं-भू सरपंच द्वारा वार्ड क्रमांक 17 में अच्छी खासी चल रही पेयजल सप्लाई को बाधित कर जेसीबी मशीन से उखड़वा दी। साथ ही नवीन पाईप लाईन डालने का ऐलान कर दिया। उखड़ी लाईन बिखरी मिट्टी के कारण कई दिनों रास्ता बंद रहा। स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बाद घटिया किस्म के पीवीसी पाईप डाले गए। यहां ये भी एक जांच का विषय है कि स्वयं-भू सरपंच द्वारा बगैर किसी शासकीय तकनीक अधिकारी की उपस्थिति के बगैर ये पीवीसी लाईन डाली गई। लाइन डालते वक्त अपने बड़बोले समर्थकों से पूरे मोहल्ले में कहलवाया गया कि ये लाईन दस पन्द्रह दिन और नहीं डलती वह तो सरपंच ने अपनी जेब से पैसा खर्च कर काम करवा रहा है। घबराई और परेशान जनता ने घटिया किस्म की पाईप लाईन का विरोध करने के बजाए चुप रहने में अपनी भलाई समझी। कई लोगों ने कहा कि विरोध करा तो ये गड्ढे और मिट्टी ऐसे महीने भर तक ऐसे घर के सामने पड़े रहेंगे और जानबूझकर ये पंचायत वाले और परेशान करेंगे। घर में रहने वाले बच्चों और बड़े बुजुर्गों की चिन्ता करते हुए मोहल्ले वाले कुछ नहीं बोले। र ग्राम पंचायत बामनिया के कर्ताधर्ताओं ने अपना काम बता दिया। अब शुरू हुआ कमाई का खेल। बाहर गांव के कुछ लोग आकर नल कनेक्शन जोड़ने लगे। आमजनता को लगा चलों कुछ तो अच्छा काम कर रही हैं पंचायत,स लेकिन आपदा को कमाई का अवसर बनाने वाली बामनिया पंचायत ने प्रति कनेक्शन 500 रुपए शुल्क वसूलना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में आम मतदाता अपने को ठगा-सा महसूस करने लगा। एक तो कोरोना महामारी में लॉक डाउन के कारण कामकाज वैसे सभी बंद पड़े। आर्थिक स्थिति चरमरा रही हैं और ऐसे में 500 रुपए की अवैध उगाही पंचायत की सिर पर आ गई। मोहल्ले के लोगों ने विरोध किया, तो जल व्यवस्था ठप करने की धमकी दी गई और चेतावनी दी कि जब तक एक भी कनेक्शन के पैसे बाकी रहेंगे पाईप लाईन को मुख्य जलप्रदाय लाईन से नही जोड़ा जाएगा। परिणाम भी वैसा ही सामने आया। पाईप लाईन को मुख्य लाइन से विगत छह दिनों से जोड़ा नहीं गया है। रोज उपभोक्ताओं पर पैसे देने का दबाव बनाया जा रहा है। नहीं तो कनेक्शन काटने की धमकी दी जा रही है। जबकि देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी ने आमजनता को आर्थिक सहायता प्रदान करने की रोज घोषणा हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा रोज सोशल मीडिया पर आम नागरिकों को पैसे के लिए परेशान नहीं करने की अपील की जा रही हैं। ऐसे में भाजपा के बैनर तले जितने वाला सरपंच खुद अपने मुख्यमंत्री की अपील ठुकराकर अवैध वसूली में लगे है। जिससे आम नागरिकों में सरपंच और भाजपा दोनों के प्रति आक्रोश व्याप हो रहा है जिसका परिणाम आगामी चुनाव में पार्टी को भुगतना पड़ेगा तय है।

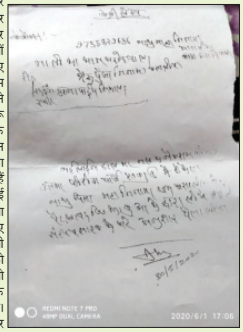

आरटीआई एक्टविस्ट सुरेश चोरडिया द्वारा लिखित में 500 रुपए की प्राप्ति रसीद ली गई है। जिसमें प्लम्बर द्वारा उल्लेखित किया गया है कि सरपंच के आदेशानुसार 500 रुपए शुल्क वसूल किया जा रहा है।

पूर्व सरपंच जगदीश मीना ने बताया कि मोहल्ले के उपभोक्ताओं द्वारा पूर्व में जब कनेक्शन लिया था, तभी निर्धारित शुल्क जमा कराया गया था। पुनः नल कनेक्शन शुल्क की मांग करना ये उपभोक्ताओं के साथ अन्याय है। अगर ग्राम पंचायत बामनिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हैं और अगर अब भी उपभोक्ताओं को परेशान करना बंद नहीं किया तो में स्वयं सभी मोहल्लेवासियों को लेकर कलेक्टर से इसकी शिकायत करूंगा।

स्थानीय रहवासी खुशवंत डामर ने बताया कि लॉक डाउन के कारण काम धंधे बंद है ऐसे में ग्राम पंचायत द्वारा मदद करने के बजाय ऐसी भीषण गर्मी में लोगो को परेशान कर रही हैं और उनका आर्थिक शोषण करने पर आमादा है जो घोर निंदनीय कृत्य हैं।

सहायक सचिव भेरूलाल मैडा से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार के कोई भी नल कनेक्शन शुल्क वार्ड नं 17 में नही लिया जा रहा है मुझे आपके द्वारा बताने पर ही पता चला है में सरपंच मैडम से बात कर के आपको बताता हूं लेकिन काफी इंतजार के बाद भी सचिव का जवाब नही आना मतलब दाल में कुछ काला है।

राष्ट्रीय गौ सेवा संघ देशभर में 10 जून तक चलाएगा नांद अभियान

माही की गूंज, झाबुआ। राष्ट्रीय गौ सेवा संघ द्वारा चलाए जा रहे नांद अभियान सहित कई महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में राष्ट्रीय तथा प्रदेश के पदाधिकारियों की एक विशेष बैठक वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सम्पन्न हुई। बैठक में राष्ट्रीय गौ सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश मानसिहंका ने कहा कि राष्ट्रीय गौ सेवा संघ सामाजिक कार्यो के साथ-साथ अपने युवा कार्यकर्ताओं के लिए स्टार्ट अपन तथा अन्य माध्यमों से रोजगार के लिये भी तैयारी कर रहा है। शीघ्र ही गौ शालाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कई उत्पादको को जनता को समर्पृत् ककिया जाएगा। प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर लोकल फॉर वोकल को सफल बनाने हेतु युवाओ को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय सगठन मंत्री दिलीप धनराज गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय गौव सेवा संघ आप सबके सहयोग से 10 राज्यो में जिला स्तार तक कार्यरत है। हमें अब अपनी सक्रियता से मंडल स्तर तक इस अभियान को ले जाना है। राष्ट्रीय गौ सेवा संघ पूरे भारत मे गौ माता की जल सेवा हेतु है। नांद अभियान का पखवाड़ा 2 से 10 जून तक मनाएगी। 2 जून को प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक देशभर के कार्यकर्ताओ अपने ट्वीट पर नांद अभिया के माध्यम से ट्वीट करके अपने फोटो एवं वीडियो भेजे। इस अवसर पर बैठक मे राष्ट्रीय सचिव मनोहर जायसवाल, राष्ट्रीय मत्री शैलेन्द्र तेगरिया, राष्ट्रीय प्रचार प्रसार प्रमुख अनुज शर्मा आदि उपस्थित थे।

आजाद अध्यापक संघ ने मांगों को लेकर बीईओ को दिया ज्ञापन

माही की गूंज, थांदला। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने बुधवार को विकास खंड कार्यालय थांदला पर उपस्थित होकर बीईओ दयाराम सोलंकी को आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमें अध्यापकों ने कई प्रकार की समस्याएं का उल्लेख किया। जिसमें बताया कि जनजातीय कार्य विभाग झाबुआ से 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके अध्यापकों के क्रमोन्नति आदेश 28 .01 2020 को जारी हो चुके हैं, किंतु आज दिनांक तक क्रमोन्नति वेतन प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे समस्त अध्यापकों को क्रमोन्नति वेतन इसी माह दिया जाए। साथ ही प्रतिनियुक्ति वाले और बिना एम्पलाई कोड वाले अध्यापक को संविदा शिक्षक को गुरुजी एवं अन्य अध्यापकों के साथ प्रति माह वेतन का भुगतान किया जाए। वर्ष 2015 की हड़ताल अवधि का वेतन आदेश हो जाने के बाद भी आज दिनांक तक नहीं दिया गया। जैन अध्यापकों के एम्पलाई कोड जारी नहीं हुए हैं। उनके डीडीओ से एम्पलाई कोड जारी कर सातवें वेतन का भुगतान किया जाए। इस प्रकार अनेक समस्याओं का ज्ञापन बीईओ को दिया गया। ज्ञापन देने वालों में जिला उपाध्यक्ष सुवाल बारिया, जिला सचिव जवान सिंह बारिया, ब्लॉक अध्यक्ष मिट्ठू सिंह गणावा, प्रवीण पण्डा, मेताान डामोर, करण सिंह खोखर, उदय सिंह, तोलिया कतीजा आदि उपस्थित थे।

कांग्रेस का आरोप, भाजपा शासन में स्थानांतरण उद्योग फल फुल रहा

माही की गूंज, झाबुआ। प्रदेश सहित झाबुआ जिले में भाजपा सरकार के सान्निध्य में स्थानान्तर उद्योग तेजी से फल फूल रहा है। जिले के भाजपा वरिष्ठ नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों के यहां कर्मचारीयों की भीड़ प्रतिदिन लग रही है। भाजपा के छुटभैया नेता आये दिन कर्मचारीयों से धोस धपट कर स्थानान्तर की धमकी दे रहे हैं। तथा अनेक कर्मचारीयों से राशि लेकर स्वेच्छिक स्थानान्तर भी कराये जा रहे हैं।

उक्त आरोप झाबुआ-अलीराजपुर जिले के विधायकगण कांतिलाल भूरिया झाबुआ, वीरसिंह भूरिया थांदला, वालसिंह मेड़ा पेटलावद, कलावती भूरिया जोबट एवं मुकेश पटेल अलीराजपुर ने लगाते हुए कहा कि भोपाल सहित म.प्र के अन्य जिलों में भी कोरोना महामारी के चलते अनेक स्थानानतर किये गये हैं तथा अभी भी स्थानान्तर उद्योग धडल्ले से चल रहा है। जहां एक ओर जनता बेरोजगारी, काम धंधे छुटने से परेशान है, वहीं कर्मचारीयों में भी स्थानान्तर का भय बना हुआ है जिले के अनेक भाजपा नेता अपने-अपने जुगाड़ में लगे हुए है। तथा पूरे झाबुआ अलीराजपुर जिले के नेतागण भोपाल में अपने कर्मचारीयों के स्थानान्तरण करने एवं निरस्त करने की दौड़ लगा रहे हैं। इस सबंध में झाबुआ अलीराजपुर के जिले के विधायकों ने मांग की है कि तत्काल रोजगार एवं पीने के पानी की समस्याओं पर ध्यान दिया जावे अन्यथा दोनों जिलों में एक साथ कांग्रेस विरोध करेगी एवं भाजपा सरकार की विफलताओं को आमजनता कों अवगत कराया जाएगा।

अगले 24 घंटे में तेज हवाओं के साथ हो सकती है वर्षा

माही की गूंज, झाबुआ। प्रदेश में महाराष्ट्र तथा गुजरात की ओर टकराने वाले निसर्ग तुफान का प्रभाव मप्र के इन्दौर, उज्जैन संभाग में असर दिखाई देगा। जिसमें 50 किमी प्रतिघंटा की गति से तेज हवाएं चलेगी। गरज व चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना एव भारी बारिश की सभावनाएं व्यक्त की जा रही है। झाबुआ मौसम विभाग के अनुसार निसर्ग तुफान का झाबुआ जिले में अभी कुछ असर संभवतः नहीं होगा। अभी 12 से 24 घंटे तक हो सकता है तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावाएं देखी जा रही है। वही निसर्ग तुफान का अगले 12 से 24 घटे में कोई बड़ा प्रभाव नहीं दिखेगा।

जिले में वर्षा की स्थिति

जिले में इस वर्ष 1 जून से अब तक 3.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दौरान झाबुआ में 6.0 मिमी, रामा में 5.0 मिमी, पेटलावद में 3.2 मिमी तथा राणापुर में 5.0 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई है।

रमेश लोहार हुए सेवानिवृत्त

माही की गूंज, खवासा। खवासा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्रेसर के पद पर पदस्थ रमेश लोहार अपनी 40 वर्ष की नौकरी को पूर्ण कर 30 मई को सेवानिवृत्त हुए। लोहार की सेवानिवृत्ति पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर गुर्जर सहित स्टाफ ने विदाई समारोह रख शाल-श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया।

इस अवसर पर सेवानिवृत्त रमेश लोहार ने कहा कि पूरी ईमानदारी के साथ जीवन के 40 वर्ष स्वास्थ्य सेवा में दिए, सेवानिवृत्त होने के बाद अब गांव व समाज में अपनी सामाजिक सेवा दूंगा।

जिला पंचायत सीईओ संदीप शर्मा के दावों की पोल खोलती शिकायत

बाछीखेड़ा पंचायत के ग्रामीणों को पूरे लॉकडाउन में नही मिली एक भी दिन मजदूरी

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश मेहलोत

देश में कोरोना वाइरस (कोविड-19) संक्रमण के बाद लॉक डाउन के कारण देश भर के गरीब मजदूरों के रोजी रोटी के संकट पैदा हो गया था। झाबुआ जिला आदिवासी बहुल हो कर यहां का अधिकांश ग्रामीण वर्ग खेती और मजदूरी पर आधारित हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने लॉक डाउन 2.0 के बाद जिले भर में मजदूरों को रोजगार देने के उद्देश्य से मनरेगा के कई कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर शुरू करने के आदेश जारी किए। जिसकी मॉनिटरिंग जिला पंचायत सीईओ संदीप शर्मा को करानी थी। सीईओ शर्मा ने पेटलावद विकास खण्ड के कुछ एक पंचायतों को टारगेट कर महीने में दस चक्कर लगाये और मनरेगा के कार्य शुरू कर दिए। पूरे विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों में मनरेगा के माध्यम से पेटलावद विकास खण्ड में 15 हजार से भी ज्यादा मजदूरों को रोजगार देने के दावें भरते हुए समाचार प्रकाशित करवा लिए, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें बड़ी पंचायतें भी शामिल हैं। जहां लॉकडाउन 3.0 से कोई नया कार्य शुरू नहीं किया न ही पुराने अधूरे कार्य शुरू किए गए। आलम ये हैं विकास खण्ड के कई पंचायतों में कोई नया कार्य नहीं खुला और जिन पंचायतों में कार्य शुरू हुए, वहां मौके पर कम और कागजों पर ज्यादा मजदूर चल रहे हैं। जिसको देखने वाला कोई नहीं। शिकायत के बाद भी भ्रष्ट पंचायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही हैं।

बाछिखेड़ा पंचायत के ग्रामीणों ने की शिकायत- नहीं मिली मजदूरी

ग्राम पंचायत बाछिखेड़ा के अमृतलाल भाबर और कुछ मजदूरों ने जनपद सीईओ को लॉक डाउन के दौरान ग्राम पंचायत ग्वालरुंडी और कतीजपाड़ा गाव के लोगों को लॉक डाउन के 60 दिनों में एक भी दिन रोजगार नहीं दिया गया। शिकायतकर्ता अमृतलाल भाभर ने बताया कि गांव के लोग ज्यादातर बाहर मजदूरी पर थे, जो घर लौट गए सरकार मजदूरी देने के दावे कर रही हैं, लेकिन हमारे दोनो गांव के लोगों को अभी तक कोई मजदूरी नहीं मिली। दोनों गांव में लभगभ 300 से 350 जॉब कार्ड खाली पड़े हैं। एक भी दिन मजदूरी नहीं दी गई है। वहीं मजदूरी नहीं मिलने से परेशान प्रेमसिंह ने बताया की कुछ ही दिनों में बारिश हो जाएगी और खेत तैयार करने का कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे में मजदूरी नहीं मिलने से खेत में फसल बोने के लिए बीज खरीदने तक के पैसे नहीं है। बाछिखेड़ा तो केवल उदाहरण हैं, जहां रोजगार के लिए काम शुरू नहीं किए गए और दिखावे और वाहवाही लुटने के आंकड़े अपने अधिकारियों को परोस दिए गए।

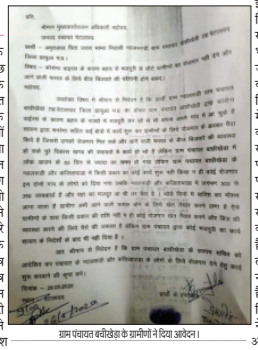

ग्राम पंचायत बवीखेड़ा के ग्रामीणों ने दिया आवेदन।

शिकायतों और नये काम के लिए हो रही वसूली

जिला सीईओ पर ग्राम पंचायतों से वसूली करने का आरोप नया नहीं है और इसमें किसी को संशय भी नहीं है कि जिला सीईओ पेटलावद विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों में मचे भ्रष्टाचार के लगातार हो रहे खुलासे पर जांच और कार्यवाही के नाम पर वसूली कर रहे है। क्योंकि ऑफ दी रिकॉर्ड हुए भ्रष्टाचार के एक भी मामले में अब तक कोई बड़ी कार्यवाही नहीं की गई। अब तो ग्राम पंचायतों के सचिव साहब की वसूली से इतने परेशान हो गए कि खबर छापने वाले पत्रकार को पैसे देकर खबर रोकने का खुला ऑफ दे रहे हैं। जिसके पीछे सचिव सरपंच को भ्रष्टाचार के मामले का डर नहीं साहब की वसूली का डर है। जो 50 हजार से शुरू कर 02 लाख तक पहुंच रही है।। जिसकी एक नहीं चार काल रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। एक सचिव ने तो यहां तक बताया कि पिछले दिनों पेटलावद आए साहब ने पेटलावद जनपद सीईओ के ऑफिस में बैठ के दस हजार से 25 हजार रुपए ग्राम पंचायत के सचिव को एक-एक कर अंदर बुलाकर ये कह कर वसूले कि अगर में ग्राम पंचायत में नहीं आंऊ तो यहां आकर पैसे देने होंगे। डरे चमके कई सचिव अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए ताबड़तोड़ बाजार से अपने मिलने वालों से हाथ उधार पैसे लेकर साब की भेंट पूजा करके आए।

पत्रकारो को खुला ऑफ

पिछले दिनों जनपद पेटलावद के कार्यालय में आए जिला सीईओ शर्मा से ग्राम पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार पर सवाल करने के लिए पहुंचे पत्रकारों को झाबुआ आकर मुलाकात करने का खुला ऑफ दिया, तो साहब ने बड़ी सादगी से कहा ये सब तो चलता रहेगा आप तो झाबुआ आओ तो कुछ को कोरोना वारियर्स बता कर उनको सम्मान और सम्मान निधि के खुले ऑफ दिए गए। कुछ पत्रकार ने अपनी कलम की धींस देकर ग्राम पंचायतों में ठेके ले लिए तो कुछ ने अपनी फर्जी एजेंसी के बिल लगा कर हजारों रुपये अलग-अलग पंचायतों से ऐंठ लिए बताया जा रहा है। इसके पीछे भी सचिवों पर साहब ने कुछ पत्रकारों कि ठेके देने और उनके फर्जी बिल लगा कर उनको भुगतान करने का दबाव बनाया गया। कुछ पत्रकार गुड़ पर मक्खी की तरह साहब के आसपास मंडराते रहते है। जिसे साहब अपना जलवा समझते हैं।

पूर्व विधायक निर्मला भूरिया के सुझाव पर प्रदेश में बनेगा प्रवासी मजदूर आयोग

माही की गूंज, झाबुआ।

मजदूरों के हित संरक्षण व आपदाओं के समय त्वरित सहायता के लिए अब मप्र में प्रवासी मजदूर आयोग का गठन किया जाएगा। खास बात ये हैं कि इसके लिए पेटलावद की पूर्व विधायक निर्मला भूरिया ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की तो उन्होंने यह मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने कहा जिस तरह से उत्तरप्रदेश में प्रवासी मजदूर आयोग बनाया गया है। उसी तरह मप्र में भी इसकी आवश्यकता है। भूरिया के सुझाव को अमल में लाते हुए मुख्यमंत्री ने अलग से प्रवासी मजदूर आयोग का गठन करने की घोषणा कर दी। इसके तहत जिलास्तर पर अब प्रत्येक मजदूर का पंजीयन किया जाएगा। यदि कोई मजदूर बाहरी राज्य से जिले में आता है तो उसका भी पंजीयन होगा। जिससे आपातकाल के समय उन्हें त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। मुख्यमंत्री द्वारा प्रवासी मजदूर आयोग के गठन की घोषणा पर पूर्व विधायक निर्मला भूरिया के साथ भाजपा नेताओं व मजदूरों ने आभार व्यक्त किया है।

फाईल फोटो

साध्वीजी विधवत गुणाश्री जी का होगा झाबुआ वर्षावास

माही की गूंज, झाबुआ। स्थानीय बावन जिनालय जैन मंदिर में 2020 का वर्षावास पुण्य सम्राट श्रीमद् सुरीश्वरजी मसा के पट्टधर के परमपति गच्छाद्रिपति आचार्य देवेश श्रीमद्विजय निन्यसेन सुरीश्वरजी मासा एवं परम पूज्य आचार्य श्री जयरत्नसुरीश्वरजी मसा के अनुवर्तनी साध्वी जी विधवत गुणाश्री मसा जी आदिठाना का वर्षावास झाबुआ नगर में होगा। जिसमे जैन श्रीसंघ मे हर्ष व्याप्त है। चातुर्मास की घोषणा 31 मई को लिम्बाहेडा मे गच्छाद्रिपति नित्यसेन सुरीश्वरजी मसा ने अपने मुखाँविन से घोषणा की। 4 जुलाई से वर्षावास प्रारम्भ होगा तथा 29 नवम्बर को वर्षावास का समापन होगा। इस वर्ष अधिक मास होने पर पांच माह का वर्षावास होगा। श्रीसंघ के पूर्व अध्यक्ष बाबूलाल संघवी, धरमचंद मेहता, कांतिलाल बाबेल, राजेन्द्र मेहता, वर्तमान अध्यक्ष संजय मेहता, डॉ. प्रदीप संघवी, मुकेश जैन नाकोड़ा, राजा रूनवाल, अंतिम जैन, राजेश मेहता, रिंकु रूनवाल, जितेन्द्र जैन, मुकेश लोढा, बाबूलाल कोठरी, प्रदीप कटारिया, महिला परिषद् की राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा कटारिया, किरण भडारी, सुनिता बाबेल, अंजू भडारी, कविता मेहता ने आदि ने गच्छाद्रिपति के प्रति आभार व्यक्त किया।

अंतरराष्ट्रीय आखर आखर सम्मान से डॉ. चंचल सम्मानित

माही की गूंज, झाबुआ। साहित्यकार डॉ. रामशंकर चंचल को अंतरराष्ट्रीय हिंदी पत्रिका आखर आखर ने वर्ष 2020 का आखर सम्मान से नवाजा। डॉ. रामशंकर चंचल की हिंदी साहित्य की अमूल्य राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के लिए उन्हें यह गौरव पूर्ण महत्वपूर्ण सम्मान से सम्मानित किया। पत्रिका की मुख्य संपदिका और संचालिका डॉ. पुष्पलता अधिवक्ता ने उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया। इस चयन समिति ने 2020 के लिए आखर सम्मान से डॉक्टर चंचल को सम्मानित किया।

नगर में सोशल डिस्टेंसिंग का नही हो पा रहा पालन

हाट बाजारों की तरह दिखाई दे रही लोगों की भीड़, कही कोरोना को न्यौता ना मिल जाऐ

माही की गूंज, झाबुआ।

नगर में इन दिनो लॉकडाउन के चलते आशिक छूट दिए जाने के बाद सोश्यल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों के द्वारा ना ही मास्क का उपयोग किया जा रहा है और ना ही सोश्यल डिस्टेंसिंग का। विगत कई दिनों से आशिक छूट के बाद से नगर में कही भी सोश्यल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। विगत दिनों पूर्व ही कोरोना के 3 ओर मरीज गोपाल कॉलोनी के पॉजिटिव्ह पाए गए थे। जिस पर से अभीतक उनकी दूसरी रिपोर्ट नहीं आई है। जिस पर से झाबुआ नगर सहित पूरे जिले मे अभी भी कोरोना संक्रमण के बादल छटे नहीं है। वही दूसरी ओर नगर में पुलिस विभाग की सुस्ती भी दिखाई देने लगी है।

जिला चिकित्सालय की अगर बात कहे तो वहा पर भी मरिजों के द्वारा सोश्यल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। भविष्य में यदि कोई भी व्यक्ति यदि कोरोना संक्रमित निकलता है तो ऐसे में ना ही सिर्फ चिकित्सालय में आने वाले अन्य मरिजों को ही ना केवल जिला चिकित्सालय में कार्यरत कर्मचारियों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं जिला चिकित्सालय में अधिकारियों के द्वारा इस ओर कोई ध्यान ने देकर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा जहा एक पूरे नगर मे सुबह 8 से शाम 4 बजे तक लॉकडाउन के तहत आंशिक छूट प्रदान की गई है। जिला प्रशासन को नगर में अभी पूर्णतः छूट नहीं दी जाना चाहिए। वहीं उनके द्वारा दिए गए निर्देशो का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए। वहीं नगर में दूकानदारों की दूकानों के आगे जिला प्रशासन के सख्त निर्देशों का चस्पा करवा देना चाहिए जिसमें उपभोक्ताओ को बिना मास्क के सामानों का वितरण नहीं किया जाएगा। साथ ही सोश्यल डिस्टेंसिंग का पालन भी करने को करवाना होगी। जिला प्रशासन के निर्देशों को विगत कई दिनों से धत्ता बताया जा रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में उनका आना-जाना हो रहा है। वही बाजारों में हाट बाजार से नजार रोजाना दिखाई दे रहा है। जो कहीं कोरोना संकट को जिले से बाहर जाने के बजाए उसे न्यौता दे रहा है। इस ओर जिला प्रशासन को ध्यान देने की दरकार है।

पेयजल समस्या का तत्काल निराकरण करे- कांतिलाल भूरिया

माही की गूंज, झाबुआ। वर्तमान में जिले में पेयजल की समस्या आ रही है जिससे ग्रामीण जन परेशान है। इस सबंध में कांतिलाल भूरिया विधायक झाबुआ द्वारा कलेक्टर प्रबल सिपाहा एवं कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा से ग्रामीण क्षेत्रों में बिना किसी भेदभाव के तत्काल हेण्डपंप खनन करने सबंधी निर्देश दिए है। साथ ही कार्यपालनयंत्री से चर्चा कर उन्हे निर्देश देते हुए बताया कि जहां पर पानी की अत्यन्त समस्या है वहां तत्काल प्राथमिकता से हेण्डपंप खनन करने सबंधी चर्चा की साथ ही जिन स्थानों पर पानी नीचे चला गया है वहां पर तत्काल पाईप बढ़ाए जाने के भी मांग की है।

ढ़ाई करोड़ की योजना को लगा पलीता नगर के लोग पानी के लिए तरस रहे

माही की गूंज, सारंगी। संजय उपाध्याय

ढाई करोड़ रुपये की योजना पड़ी खटाई में सारंगी नगरवासियों को आज भी पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है। ठेकेदार की उदासीनता के चलते फिल्टर प्लांट का काम अधूरा छोड़ कर ठेकेदार फरार हो गया है। जब फिल्टर प्लांट का काम चालू हुआ था नगर के लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि अब पानी के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, लेकिन करीब 2 वर्ष हो चुके हैं। आज भी काम अधूरा पड़ा है और लोगों को पानी के लिए इस भीषण गर्मी में भटकना पड़ रहा है। लोगों को टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है जबकि सारंगी में पानी के लिए करोड़ों रुपए बर्बाद हो चुके है, लेकिन समस्या आज भी वही है। नगर में जो पुरानी पाइप लाइनें हैं, उससे पानी दिया जा रहा है। वह भी दो-चार दिन में एक टाइम पानी दिया जा रहा है। वह पानी पीने लायक तो ठीक नहाने लायक भी नहीं है। ठेकेदार की उदासीनता का परिणाम नगर की जनता भुगत रही है। नगर के लोगों का कहना है फिल्टर प्लांट का काम जल्दी से जल्दी चालू करवा कर इस समस्या का समाधान प्रशासन को करना चाहिए। लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। नगर के लोग पानी के लिए काफी परेशान हैं। जैसे-तैसे अपना काम चला रहे हैं। ठेकेदार ने नई पाइप लाइन डालने के चक्कर में नगर के पूरे बाजार में सीसी रोड को खोदकर पाइप लाइन डाली। उससे पूरे नगर में गड्ढे हो चुके हैं। पूरा सीसी रोड खत्म हो चुका है। लोगों को इससे भी काफी परेशानी हो रही है जबकि ठेकेदार को पाइप लाइन डालकर रोड को व्यवस्थित बनाना था। जब हमारे संवाददाता ने ठेकेदार से संपर्क किया तो वह फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। ठेकेदार की गलती की सजा नगर के लोग भुगत रहे हैं। क्या प्रशासन इस ओर ध्यान देकर इस फिल्टर प्लांट को चालू करवाएगे या नगर के लोगों को अपने हाल पर छोड़ देंगे।

मलेरिया निरोधक माह का शुभारंभ, अन्तरविभागीय कार्यशाला का आयोजन

माही की गूंज, झाबुआ। राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालनालय मप्र भोपाल के निर्देशानुसार 1 जून से 30 जून तक सम्पूर्ण माह को ''मलेरिया निरोधक माह'' के रूप में मनाया जाना हैं। सम्पूर्ण माह में जन जागृति हेतु विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी। इसी क्रम में सोमवार को जिला पंचायत अध्यक्ष शांति डामोर द्वारा चलित जनजागृति मलेरिया रथ को हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण एंव शहरी क्षैत्र में प्रचार-प्रसार के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात अध्यक्ष जिला पंचायत की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के आमंत्रित पदाधिकारी की एक दिवसीय 'अन्तरविभागीय कार्यशाला'' का आयोजन कोरोना वायरस को दृष्टिगत रखते हुए 'सोश्यल डिस्टेसिंग' का पालन करते हुए किया गया। कार्यशाला में नगरपालिका, नगर निकाय के प्रभारी को शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन नालियों की साफ-सफाई,अनावश्यक गड्ढे को पाटने,अवांछित जल स्त्रोत में पानी की निकासी, मच्छरजन्य परिस्थितियों का समाप्तिकरण, नालियों में कीटनाशक डालकर मच्छर उत्पत्ति स्थल के समाप्तिकरण हेतु चर्चा की गई।

कार्यशाला में डामोर, नीलम मेड़ा एसडीओ जल संसाधन विभाग, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एनके पठान, सहायक संचालक मत्स्य विभाग, यूसी भाटी, जिला मलेरिया अधिकारी, डीएस सिसोदिया, जिला सलाहकार जितेन्द्र बघेल, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, विनोद कुमार बाचें, नगरपालिका प्रतिनिधि युनुस कुरैशी, खंड चिकित्सा अधिकारी रामा एस बबेरिया, बीएस डाबर, खंड चिकित्सा अधिकारी कल्याणपुरा, डॉ. एमएल चोपड़ा, खंड चिकित्सा अधिकारी सामु.स्वा.केन्द्र पेटलावद,डॉ.अनील राठौर, मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी सामु.स्वा.केन्द्र थांदला, डॉ.शैलेक्सी वर्मा, मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी मेघनगर समस्त ब्लाक में कार्यरत मलेरिया निरोधक तथा शहर के जन प्रतिनिधि उपस्थित थे। डॉ.पठान ने आभार माना।

संपादकीय

देश खुला पर कोरोना से सतर्कता पहले से ज्यादा जरूरी

देश खुला पर कोरोना से लड़ने में सतर्कता ही प्राथमिकता देश में पांचवें लॉकडाउन का लागू होना उतना ही जरूरी हो गया था, जितना लॉकडाउन में ढील देना। कड़ाई और ढील की मिली-जुली व्यवस्था ही समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसी मजबूती की ओर संकेत करते हुए चेताया है कि देश खुल गया है, अब ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। वाकई सतर्कता आज प्राथमिकता है, तभी हम न केवल अपने कार्य-व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे, स्वयं को सुरक्षित रखने में भी कामयाब होंगे। जाहिर है, लॉकडाउन पांच पिछले लॉकडाउन की तरह नहीं है। अब केवल कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन रखना अनिवार्य होगा। साथ ही, इस बार राज्यों की भूमिका वाकई बहुत बढ़ गई है। उन्हें अपने स्तर पर बड़े फैसले करने हैं। मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार इत्यादि राज्यों ने तो लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने का फैसला कर लिया है। कुछ राज्य 15 जून तक ही लॉकडाउन के पक्ष में हैं। आज कुछ राज्य ज्यादा चिंतित हैं, तो समझा जा सकता है। पिछले लॉकडाउन की अगर हम चर्चा करें, तो 14 दिनों में ही संक्रमण के लगभग 86 हजार मामले सामने आए हैं। आंकड़ों को अलग से देखें, तो चिंता होती है, लेकिन दूसरे देशों से तुलना करें, तो अपेक्षाकृत संतोष होता है। हमारा यह संतोष कायम रहना चाहिए। यह चर्चा जारी रहेगी कि जब देश में 500 मामले भी नहीं थे, तब बहुत कड़ाई से लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन जब मामले दो लाख के करीब पहुंचने लगे है, तब लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। जब केंद्र और राज्य सरकारें ढील पर विचार कर रही थीं, तब 30 मई को संक्रमण के मामलों में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज हुआ है। अब एक दिन में 8,000 से ज्यादा मामले आने लगे है, तो आने वाले दिनों में क्या होगा? मरने वालों की संख्या भी 5,000 के पार जा चुकी है। ऐसे में, जब धर्मस्थल, रेस्तरां, होटल, शॉपिंग मॉल, स्कूल-कॉलेज खुल जाएंगे, तब क्या होगा? जब सड़कों पर सार्वजनिक वाहन दौड़ने लगेंगे, फिर क्या होगा? धर्म और शिक्षा के मंदिर देश में हमेशा से भीड़ भरे रहे हैं। ये हमारे समाज के सबसे कमजोर मोर्चे हैं, जहां संचालकों-प्रबंधकों को विशेष रूप से चौकस रहना होगा। धर्मस्थल के संचालकों की ओर से आ रहे दबाव को समझा जा सकता है, पर वहां फिजिकल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित रखना अच्छे संस्कार, सभ्यता की नई निशानी होगी। धर्म प्रेरित मानवता भी हमें एक-दूसरे की चिंता के लिए प्रेरित करती है। हम सभी न चाहते हुए भी एक-दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। कोरोना के संदर्भ में अनेक लोगों को अब यह नहीं पता चल रहा है कि उन्हें कोरोना किससे लगा? घर से निकलने वाला एक आदमी अगर अनेक लोगों के संपर्क में आएगा, तो यह पता लगाना उत्तरोत्तर कठिन होता जाएगा कि कोरोना की कौन-सी श्रृंखला आगे बढ़ रही है। लॉकडाउन पांच के समय देश ऐसी अनेक तरह की नई चुनौतियों की ओर बढ़ रहा है। संदिग्ध लोगों की निगरानी का काम हाथ-पैर फुला देगा। बेशक, अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार हम देखेंगे और देश के लोगों को राहत देने के लिए यह अपरिहार्य है। ध्यान रहे, हर जगह पुलिस या सरकार खड़ी नहीं हो सकती, हमें स्वयं अनुशासित नागरिक बनकर अपनी और अपने पास के लोगों की पहरेदारी करनी है। यह अपनी ऐसी फिक्र करने का समय है, जिसमें सबकी फिक्र शामिल हो।

अब तो व्यवस्थाओं से डर लगता है !

डॉ.अरविंद प्रेमचंद जैन, लेखक

राजा महल के दालान में टहल रहे थे, उनको एक गरीब व्यक्ति ठण्ड से काँप रहा था. राजा ने अपने नौकर से कहा की उस गरीब को ठण्ड लग रही हैं उसे कम्बल की व्यवस्था कर दो. जी हुजूर! उसने अपने तत्कालीन अधिकारी से राजा की बात पहुंचाई। अधिकारी ने मंत्री को, मंत्री ने सम्बंधित विभाग के मंत्री को सूचित किया। उस मंत्री ने वित्त विभाग से बजट माँगा, बजट की स्वीकृति पर क्रय विभाग ने आदेश जारी किया, कम्बल आया और उसकी क्रम से स्टोर में आवक जावक हुई, उसके बाद अधिकारी को और अधिकारी ने नौकर को,नौकर देते गया राज तक उसकी मौत हो चुकी थी, राजा ने मौत पर दुःख व्यक्त किया और एक जांच कमेटी बैठा दी, और उस रिपोर्ट का इंतजार अभी तक हैं और हां उसकी मौत पर राजा की तरफसे अन्तेष्ठी का पैसा जल्दी दिया गया। और उसका कोई न होने राजकीय अन्तेष्ठी हुई।

वर्तमान में हमारे देश में कुछ ऐसी ही व्यवस्था का सामना करना पद रहा हैं। वैसे काम करने वालों की ही आलोचना होती हैं। जो जितना पढ़ा लिखा उसे उतनी अधिक भ्रांतियां होती हैं। कहा भी जाता हैं बहुत अध्ययन बहुत कन्फूजन, कोई पढाई नहीं कोई कन्फूजन नहीं। शायद हमारे प्रधान सेवक कोई कन्फूजन वाले नहीं हैं। दूसरा जबरदस्त नेता होने से उनके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं। जिसने भी बोलै उसके पीछे तीन सी लग जाती हैं।

कहावत हैं मुर्ख पहले बोलते हैं फिर सोचते हैं और बुद्धिमान पहले सोचले फिर बोलते, हमारे प्रधान सेवक दोनों प्रकार से बोलते हैं जिससे कुछ तो सही निकलेगा। जो राजा मंत्रियों और सचिवों से मंत्रणा करने के बाद स्वविवेक से निर्णय लेते हैं उसके परिणाम दुखदायी होते हैं। कारण कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को खूब पहचानते हैं।

प्रधान सेवक अपने गुप्तरों पर बहुत भरोसा करते हैं और वे राजा की तीसरी आँख होती हैं उनको देश और विदेश की जानकारी पलपल की मालूम होती हैं। राजा हमारे तकनिकी में महारत रखते हैं। दिन रात मोबाइल, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंटरनेट से जुड़े भी हैं और दिन रात टी वी के माध्यम से देश की दुर्दशा की जानकारी रखते हैं, पर इस समय वे सत्ता के मोह के कारण धृतराष्ट्र बने हैं। उनको दृष्टि मिली हैं।

वह राजा झूठ का बहुत उपयोग करता हैं उससे उसके निजी भी दूर हो जाते हैं, कारण उनके झूठ का स्पष्टीकरण उनके सहायक देते हैं, वे विश्व प्रसिद्ध हो चुके और होंगे, निश्चित रूप से जैसे गाँधी के साथ गोडसे का नाम लिया जाता हैं।

विगत 2 माहों से अधिक समय हो चूका कारोड़ो प्रवासी कुशल कारीगर जो अपने घरों को जाना चाहते थे उनकी सुव्यवस्था शासन के द्वारा कहीं शुल्क शहित और रहित बिना एहितियात के जानवरों से बदतर हालत में अपनी प्रशंसा के साथ भेज रहे हैं। वे किस मानवीय विपदाओं से गुजर रहे हैं, उनके दुखों को देखकर उनको अपने सुविधायुक्त आवास में गर्मी महसूस हो रही होगी। कारण उनमे मानवीय संवेदनाएं कूट कूट कर भरी हैं।

जो राजा दिन रात शेर जैसा दहाड़ता था, आज पता नहीं शेर के ऊपर किसी और की खाल पहनकर न गुर्राता हैं और न कुछ बोलता हैं, शायद मौनी बाबा यानी मनमोहन सिंह की परम्परा का पालन कर रहे हैं। वर्तमान में देश में निहायत निराशा का वातावरण बना हुआ हैं कारण इन अव्यवस्थाओं से हजारों लोग अकाल काल के गाल में समां गए, रहिमन है गरीब की कभी न निष्फल जाए।

जब राजा अर्धावतारन का अधिकार रखता हैं तब उसे असिप्रहारन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इस समय देश में सुमंगल का वातावरण नहीं हैं। दिन रात तनाव, रोगियों का संक्रमण, मरण के अलावा अस्पतालों में डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ,दवाएं के अलावा इलाज में होने वाली अनियमितता, मरीज और मुर्दा एक साथ, भोजन व्यवस्थाओं में सुबह से किया जाने वाला इंतजाम दोपहर तक, भला हो स्वयं सेवी संस्थाओं का उन्होंने लाखों, करोड़ों को भूख से मरने से बचाया। इस समय भ्रष्टाचार का बोलबाला बहुत हैं। गंगा में सब डुबकी लगा रहे हैं कर प्रधान सेवक यदि धृतराष्ट्र बन चुके हैं तो कोई संजय से समाचार ले सकते हैं। दृष्टिविहीन हो जाना तो ठीक हैं पर मूक बधिर क्यों और कैसे बन गए।

इस समय जो अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ हैं इस कारण आंतरिक असंतोष बहुत हैं। आर्थिक पहिया धंस गया हैं। रोजगार बेरोजगार हो गए। जितना इलाज हो रहा उससे अधिक मर रहे। पर सफलता का श्रेय हासिल करने में अग्रसर। किसी ने कोई प्रमाण पत्र दिया वह उपलब्धि हो जाती हैं और यदि विशेषज्ञ सलाह दे तो वे देश द्रोही ध्वाधक।

स खलु नो राजा यो मंत्रिणोअतिक्रम्य वर्तेत।

निस्संदेह वह राजा, राजा नहीं हो सकता, जो कि हितैषी मंत्रियों के परामर्श कीसीमा का उल्लंघन करके व्यवहार करता हैं।

सुविवेचितांमन्त्रादभवत्येव कार्यसिद्धिरयादि स्वामिनो न दुराग्रहः स्यात।

यदि राजा दुराग्रही (हठी) न हो तो अच्छी तरह विचारपूर्वक की हुई मंत्रणा से अवश्य कार्य सिद्धि होती हैं। पर राजा हठी होने से असफलता का सामना कर रहे हैं। एक झूठ को कई बार बोला जाय तो वह सच लगने लगता हैं।

किसी भी आकार को प्रेम करना, असीम ईश्वर का एक झरोखा मात्र है

प्रत्येक व्यक्ति, जब तक वह ईश्वर को प्यार नहीं करता, एक प्रकार से मूर्ति पूजक है। किसी व्यक्ति या वस्तु को प्यार करना चूंकि वह उसे ईश्वर का स्मरण कराती है, यह एक गुण है, दोष नहीं। सबसे ऊंची मंजिल पर जाने के लिए व्यक्ति को अन्य मंजिलों से चढ़ कर जाना होगा। कोई भी व्यक्ति सबसे ऊंचे स्थल पर छलांग मार कर नहीं जा सकता, जैसे ईश्वर हैं। निराकार और निर्वैयक्तिक, इस रूप में उनसे प्रेम करना मनुष्यों के लिए लगभग असंभव है। पर ऐसा स्वाभाविक रूप से वे लोग कर पाते हैं, जो दिव्य पूर्णता को किसी मानव रूप में देखते हैं। इस प्रकार की पूजा या भक्ति में यह सदा स्मरण रखना व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है कि वह जिस आकार को प्रेम करता है, वह उस असीम ईश्वर का एक झरोखा मात्र है। इच्छा को, विशेष रूप से जहां तक तीव्र इच्छा का संबंध है, स्वयं में पहचानना बहुत कठिन है। किसी आकस्मिक लालसा से व्यक्ति का विवेक क्षण भर में ही हर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में बुद्धिमत्तापूर्ण आचरण की कुंजी है कि व्यक्ति अपने ह्रदय की भावनाओं का निरीक्षण करे।

चाणक्य नीति

आचार्य चाणक्य ने स्वाध्याय के महत्व को बहुत सुंदर शब्दों में स्पष्ट किया है। वह कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। उसे प्रतिदिन शास्त्रों का कम से कम एक श्लोक, आधा श्लोक या आधे का आधा श्लोक अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे व्यक्ति का भला होता है। ऐसा न कर पाने की अवस्था में वे कहते हैं कि दान करके अपने दिन को सफल बनाना चाहिए।

नई मुसीबत में फंस गए ट्रंप

डॉ. वेद प्रताप वैदिक

अजीब मुसीबत में फंस गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ! अमेरिका के लगभग सभी बड़े शहरों में उनके खिलाफप्रदर्शन हो रहे हैं। वाशिंगटन डी.सी. में तो व्हाइट हाउस को हजारों लोगों ने ऐसा घेरा कि ट्रंप डर के मारे अभेद्य बंकर में जा छुपे। दर्जनों लोग इन प्रदर्शनों में मारे जा चुके हैं। सैकड़ों भवनों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है। लोगों ने दुकानों और घरों में घुसकर सामान लूट लिया है।

ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को 10 साल की गिरफ्तारी, लाठियों और गोलियों का डर भी दिखा दिया है। विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को इस अराजकता के लिए वे दोषी ठहरा रहे हैं। अमेरिका-जैसे संपन्न और सुशिक्षित देश में यह सब क्यों हो रहा है ? खास तौर से तब जबकि कोरोना से हताहत होनेवालों की संख्या दुनिया में वहीं सबसे ज्यादा है ? इसका कारण वैसे तो मामूली दिखाई पड़ता है लेकिन है, वह बहुत गहरा।

अभी तो हुआ यह कि मिनियापॉलिस के एक गोरे पुलिस अफसर ने एक अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लाएड को जमीन पर पटककर उसके गले को घुटने से इतनी देर तक दबाए रखा कि उसने दम तोड़ दिया। वह चिल्लाता रहा कि उसका दम घुट रहा है लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। इस जानलेवा दुर्घटना का वीडियो जैसे ही सारी दुनिया में फैला, प्रदर्शन भड़क उठे। उनमें गोरे और काले सभी शामिल हैं। ये प्रदर्शन सिर्फअमेरिका में ही नहीं हो रहे हैं, आस्ट्रेलिया, ईरान, यूरोपीय और इस्लामी देशों में भी हो रहे हैं। जार्ज का दोष यह बताया जाता है कि वह 20 डॉलर का नकली नोट चलाने की कोशिश कर रहा था।

अमेरिका के 33 करोड़ लोगों में अश्वेतों की संख्या 4 करोड़ के करीब है। ये लोग विपन्न, वंचित और उपेक्षित हैं। ज्यादातर हाड़तोड़ काम यही लोग करते हैं। गरीबी के साथ-साथ ये लोग अशिक्षा और गंदगी के भी शिकार होते हैं। अभी कोरोना से हताहत होनेवालों में भी ज्यादा संख्या इन्हीं की है। अमेरिका में हो रही कोरोना मौतों का 50 प्रतिशत अश्वेतों का है जबकि गोरों का प्रतिशत सिर्फ20 प्रतिशत है। अमेरिका की जेलें भी अश्वेतों से भरी रहती हैं। अब से 51 साल पहले जब मैं न्यूयार्क की कोलंबिया युनिवर्सिटी में पढ़ता था, तब मेरी कक्षा में एक भी छात्र या एक भी शिक्षक अश्वेत नहीं होता था। बराक ओबामा अश्वेत होते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जरुर बन गए लेकिन मार्टिन लुथर किंग के बलिदान के बावजूद अमेरिका में आज तक अश्वेतों को बराबरी का दर्जा नहीं मिला है। ट्रंप को अश्वेत लोगों की खास परवाह नहीं है। वे गोरों के थोक वोट के दम पर जीते हैं। इस घटना को वे अपने पक्ष में भुनाने से बाज नहीं आएंगे। वे इन प्रदर्शनों को भड़काने का दोष 'अतिफ्र' नामक वामपंथी संगठन के मत्थे मढ़ रहे हैं। लेकिन इतने व्यापक अश्वेत हिंसक प्रदर्शन अमेरिका में पहली बार हो रहे हैं।

मेक इन इंडिया के नाम पर विदेशी कंपनियों के हवाले भारत?

सनत कुमार जैन, लेखक

वक्त तेजी के साथ बदल रहा है। स्वदेशी के नाम पर विदेशी कंपनियां बड़ी तेजी के साथ भारत के कारोबार में घुसपैठ कर रही हैं। कोरोनावायरस संक्रमण के समय विदेशी कंपनियों की जैसे लाटरी खुल गई है। सरकार भी इनके ऊपर मेहरबान है। लोगों को घरों में कैद करके रख दिया गया है। वहीं विदेशी कंपनियां लोगों को घर घर में सामान पहुंचा कर अथवा घर-घर में मनोरंजन कर भारी पैसा कमा रही हैं।

लाकडाउन का फायदा उठाते हुए, विदेशी कंपनियां, जिनमें चीन की अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, अमेजान, अलीबाबा, ब्रेपडील, जोमैटो, स्विगी, उबेर इटस, जैसी दर्जनों कंपनियां स्मार्टफोन और मोबाइल के माध्यम से अपने कारोबार को बड़ी तेजी के साथ बढ़ा रही हैं। डिजिटल कंपनियां भारत में अगले दो-तीन साल के अंदर 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करेंगी। भारतीय कारोबार में उनका एकाधिकार होगा। बेरोजगारी बढ़ेगी, भारतीय कंपनियां और भारतीय कारोबारी धीरे धीरे परिदृश्य से बाहर हो जाएंगे। इस काम में भारत के बड़े-बड़े उद्योगपति भी डिजिटल कंपनियों के साथ साझेदारी करके, उनका निवेश कराकर, कानूनों से बचने और टैक्स के लाभ लेने के लिए आगे आ गए हैं। जिसके कारण स्थिति दिनों-दिन भयावह होती जा रही है।

लॉकडाउन के कारण पिछले 2 माह से भारत के बाजार, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर, किराने की दुकानें, कपड़ों की दुकाने सब बंद है। लाकडाउन के दौरान जिला प्रशासन, राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार ने डिजिटल कंपनियों के माध्यम से घर-घर तक सामान पहुंचाने के नाम पर इन्हें हर भारतीय के घर में भेजने का जुगाड़ कर दिया है। भारतीय कंपनियों के लिए जो चीजें कानूनी रूप से प्रतिबंधित की गई है। विदेशी कंपनियों एवं कारपोरेट जगत की कंपनियों के लिए यह कानून लागू नहीं होते हैं। नेटफ्लेक्स में जो फिल्में आ रही है। उसमें अश्लीलता नशा, शराब, पोर्न फिल्में, घर-घर पहुंच गई है। शराब की सप्लाई किराना, साग, सब्जी, कपड़ा इत्यादि बड़े पैमाने पर यह डिजिटल कंपनियां सप्लाई कर रही हैं। 137 करोड़ की आबादी वाले भारत में कोरोना संक्रमण के दौरान इन्हें बड़ी तेजी के साथ पैर फैलाने की अनुमति केन्द्र राज्य सरकारों एवं जिला प्रशासन ने दी है। बेहिसाब और बेलगाम विदेशी डिजिटल कंपनियों की लाकडाउन में पो-बारह हो गई हैं। बुजुर्ग कहा करते थे, भारत में पहले, फ्री में लिफ्टन, और बुक ब्रांड जैसी कंपनियां बाजार और दुकानों में जाकर फ्री में चाय पिलाते थे। बाद में जब लोगों की आदत पड़ गई, तो इन्हीं कंपनियों ने करोड़ों रुपए का कारोबार करना शुरू कर दिया था। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। जिसने भारत को अपना गुलाम बना लिया था। भारत के सारे राजा-महाराजा ईस्ट इंडिया कम्पनी के कर्जदार हो गए थे। उसके पीछे अंग्रेजों का शासन आ गया था। अब ऑनलाइन डिजिटल विदेशी कंपनियों के ऊपर सरकार की मेहरबानी से, भारतीय उद्योगपति, कारोबारी, सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग गुलामी और बेरोजगारी की ओर तेजी के साथ आगे बढ़कर विदेशी कंपनियों की गुलामी स्वीकार कर रहे हैं।

मीडिया के क्षेत्र में भी डिजिटल कंपनियों ने बड़ी तेजी के साथ अपना एकाधिकार बना लिया है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया है। वह भी अपने सबसे भयावह संकट के दौर से गुजर रहा है। फेसबुक गूगल और यूट्यूब जैसी कंपनियां भारतीय अखबारों और टेलीविजन चौनलों के कंटेंट से प्रतिमाह करोड़ों रुपए कमा रही हैं। लेकिन इस कमाई में से भारतीय समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चौनल को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। उल्टा घाटे के कारण मीडिया अपने अस्तित्व बनाए रखने के संकट से अब जूझ रहे हैं।

भारत सरकार, पिछले एक दशक में विदेशी डिजिटल कंपनियों के कारोबार और व्यापार के लिए कोई कानून नहीं बना सकी। उल्टे भारत में निवेश करने पर इन्हें तरह तरह की छूट दी जा रही है। इन विदेशी कंपनियों पर भारतीय कानून लागू नहीं हो पा रहे हैं। जिसके कारण नशीली दवाइयां, अश्लीलता वाली फिल्में, शराब, हिंसक जानकारियां, बाजारबाद के सहारे किराना, सब्जी, जनरल स्टोर्स, कपड़े इलेक्ट्रानिक आईटम नेटवर्क की सहायता से छोटे-छोटे नगरों तक इन विदेशी कंपनियों द्वारा घर-घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जो लाकडाउन लगाया गया है। उसके बाद इन विदेशी कंपनियों को भारत में बड़ी तेजी के साथ अपना कारोबार और अपना नेटवर्क फैलाकर एकाधिकार करने का मौका मिल गया है। जिसके कारण भारत के करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए है। भारतीय कारोबार एवं सामाजिक व्यवस्था की जो चेन बनी हुई थी। वह लाकडाउन के दौरान टूटकर बुरी तरह बिखर गई है। केंद्र एवं राज्य सरकारों में बैठे राजनेताओं और बड़े-बड़े अधिकारियों की कृपा से विदेशी डिजिटल कंपनियां बड़ी तेजी के साथ अपने कारोबार का विस्तार कर भारी कमाई कर रही हैं। संसद, विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट, कैग, आयकर प्रवर्तन निदेशालय इत्यादि कब अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे? राष्ट्रीयता के नाम पर, मेक इन इंडिया के नाम पर जिस तरह से विदेशी डिजिटल कंपनियां और विदेशी कंपनियों को भारत में लाया जा रहा है, यह आश्चर्यजनक है। भारतीय कंपनियों के लिए भारी टेक्स और कानूनों का मकड़जाल बुना गया है। वहीं विदेशी कंपनियों को पूरी छूट दी गई है। जिसके कारण भारत के परम्परागत उद्योग एवं सप्लाई चेन समाप्त हो रही है। विदेशी कंपनियों का एकाधिकार हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा राष्ट्रीयता के नाम पर इनका हमेशा से विरोध करते थे। स्वदेशी जागरण मंच सरीके संघ के अनुवांशिक संगठन अब नेपथ्य में चले गए हैं। इससे बेरोजगारी एवं अर्थव्यवस्था को लेकर भारत की चिंताएं और भी बढ़ गई है।

आकंड़ों में हेराफेरी आखिर क्यों?

क्या कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत और पीड़ित लोगों की असली संख्या सरकारें देश को नहीं बता रही हैं? ये सवाल कुछ समय पहले अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट से उठा था। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि दिल्ली के अलग- अलग अस्पतालों में मौत का जो आंकड़ा दर्ज है उसका कुल योग उस संख्या से काफी ज्यादा है, जो दिल्ली अपनी ब्रीफिंग में बताती है। फिर ये सवाल गुजरात हाई कोर्ट में उठा, जब वहां गुजरात सरकार की ओर से दलील दी गई कि अगर सबकी जांच हो तो सत्तर फैसदी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे। उससे घबराहट फैलेगी, इसलिए सीमित जांच ही की जा रही है। इस पर गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जोरदार फटकार लगाई और सबकी जांच करने का आदेश दिया।

अब इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट कहा है कि मृतकों की संख्या बताने में दिल्ली और कई दूसरे राज्य पारदर्शिता नहीं बरत रहे हैं। अगर यह बात सच है तो इसका अर्थ है कि देश में कोरोना महामारी की हालत उससे कहीं ज्यादा गंभीर और भयावह है, जितना आम तौर पर समझा जा रहा है। अगर यह सच है तो उससे सरकारों के रवैये पर गंभीर सवाल उठेगा। सवाल सिर्फ लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार का नहीं है, बल्कि जानबूझ कर अगर संख्या नहीं बताई जा रही है तो इसे अमानवीय रुख भी कहा जाएगा। जो बताया गया है कि उसके मुताबिक अब देश में रोज साढ़े सात हजार से भी ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। मौतों के मामले में संख्या चीन में कोरोना से मरे कुल लोगों की संख्या को पार कर चुकी है। भारत कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में नौवें स्थान पर आ चुका है और जल्द ही ये जर्मनी को पीछे छोड़ कर आठवें स्थान पर आ सकता है। बल्कि उसके बाद सातवें नंबर पर मौजूद फ्रांस से भी भारता फासला बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। कुल मृतकों में से तकरीबन आधे लोग महाराष्ट्र में मरे हैं। महाराष्ट्र इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। तमिलनाडु और दिल्ली का नंबर उसके बाद है। बहरहाल, सवाल यह है कि अगर सचमुच पूरे आंकड़े नहीं बताए गए हैं तो आखिर स्थिति कितनी गंभीर है, अब लोग इस पर अटकलें लगाएंगे। इसलिए बेहतर होगा, सरकारें पारदर्शिता दिखाते हुए असली सूरत दिखाएं, भले वह कितनी ही डरावना ना हो।

काम की बात

मै हर कदम पर हारा हूं, पर जन्मा केवल जीत के लिए हूं। एमर्सन

एक सलाह

बिना विश्वास के कोई काम हो ही नहीं सकता।

भारत-नेपाल पुनः समवेत, चीन हुआ अप्रासंगिक

श्रवण गर्ग, लेखक

1962 से 1967 वाला हठधर्मी चीन भारत के प्रति 1998 मे सुधरा था और इसे सुधारा था पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी जी ने, जो कि भारत चीन संबन्धो के सच्चे वास्तुकार कहे जाते हैं। वर्तमान मे भारत चीन सम्बंध मे जो भी सत्य है वह 1998 के परमाणु विस्फोट से लेकर 2003 तक के अटलबिहारी शासन की ही देन है। यह बात भारत ही नहीं चीन भी स्वीकारता है। चीन यह भी स्वीकारता है कि यदि चीन के प्रति पंडित नेहरू की गलतियों को सुधारने वाले अटल अभियान का सच्चा उत्तराधिकारी भारत को नरेंद्र मोदी के रूप मे मिल गया है। 2004 से लेकर 2014 तक का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कालखंड पुनः चीन के भारत पर हावी होने का दशक रहा। मनमोहन की कमजोर केंद्र सरकार ने चीन को अनावश्यक ही दसियों अवसरों पर भारत के प्रति आक्रामक होने का अवसर दिया। इस मध्य अनेकों गलतियां हुई जिनसे भारत चीन सम्बन्धों मे चीन के हावी होने का वातावरण बना।

मई 2020 का अंतिम सप्ताह भारत-चीन-नेपाल-पाकिस्तान के चतुष्कोण मे सदैव स्मरणीय रहेगा। मई प्रारंभ से ही लद्दाख सीमा पर चीन ने अपनी नीयत बिगाड़ ली थी। चीन ने कोरोना वायरस को फैलाने के विश्व भर से अपने ऊपर लगते आरोपों के मध्य चीन ने भारत को घेरने की कूटनीति मे नेपाल व पाकिस्तान का सहारा लिया। भारत ने चीन नेपाल पाकिस्तान के इस संयुक्त हमले को अपनी राजनयिक कौशल से छिन्न भिन्न कर दिया है। लद्दाख मे भारत चीन सीमा विवाद मे ये अंततः ये तीनों ही देश अपने कदम वापिस लेते दिखाई दिये। चीन ने भारत स्थित अपने दूतावास से दर्शनिक प्रकार के शांति संदेश दिये। नेपाल ने नक्शा विवाद मामले में विधेयक वापस ले लिया और भारत नेपाल सीमा विवाद पर चुप्पी साध ली। भारत ने अपनी सेना को लद्दाख मोर्चे पर तैनात करना प्रारम्भ करके जो सख्त संदेश व दृढ़ मानस बताया उसे चीन ने तुरंत ही समझ लिया और कहा -चाइनीज ड्रैगन और भारतीय हाथी एक साथ नृत्य कर सकते हैं। सर्वाधिक सुखकर विषय नेपाली संसद मे भारत को मिले समर्थन का दिखना रहा जिसमें अंततः संसद मे प्रस्तुत नक्शा नेपाल सरकार ने वापिस ले लिया। भारत नेपाल मे तब तनाव आ गया था जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आठ मई को उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे को धारचुला से जोड़ने वाली रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था। नेपाल ने इस सड़क के उद्घाटन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया था कि यह नेपाली सीमा से होकर जाती है।भारत ने नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा था कि सड़क पूरी तरह से उसकी सीमा में है। नेपाल की इस भूमिका के पीछे चीन का हाथ माना जा रहा था क्योंकि ओली के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टीकी नेपाल सरकार को चीन का समर्थक माना जाता है। लद्दाख मे भारत चीन तनाव व भारत नेपाल के इस कटुक संवाद के मध्य चीन के पिछलग्गू पाकिस्तान ने भी चीन के संकेत पर अपने बेसुरा आलाप प्रारंभ किया था। पाकिस्तान ने भारत पर सीमावर्ती क्षेत्रों मे अवैध निर्माण का आरोप लगाया। पाकिस्तान प्रमुख इमरान खान ने ट्वीट किया हिंदुत्ववादी मोदी सरकार की अभिमानी विस्तारवादी नीतियां नाजी विचारधारा के समान है।पाक ने यह भी कहा कि भारत अपने पड़ोसियों के लिए भी खतरा बन रहा है। भारत के खिलाफनेपाल को समर्थन देने वाला पाकिस्तान लद्दाख में भी अपने आका चीन के पीछे खड़ा होकर गीदड़ भभकी कर रहा है।

पाकिस्तान ने कहा कि भारत लद्दाख में जो कर रहा है, उसे चीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, और यह भी कहा कि चीन से वर्तमान संघर्ष के लिए भारत जिम्मेदार है, क्योंकि लद्दाख में उसकी ओर से शुरू किए गए अवैध निर्माण कार्य के बाद ही इस विवाद की जड़ है। वस्तुतः नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की बड़ी दीर्घ दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्रों मे चल रहे निर्माण कार्यों को चीन स्वाभाविक ही गंभीरता से ले रहा है व इस संघर्ष मे पाकिस्तान व नेपाल को मोहरा बना रहा है। मोहरा बने पाकिस्तान ने भारत को पड़ोसियों के प्रति खतरा बताते हुये नेपाल को भारत से नाराज करने का अभियान चला रहा है। नागरिकता कानून व कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर भी पाकिस्तान बड़ी बयानबाजी करता रहा है व बांग्लादेश को भी भड़काते रहा है। मोदी सरकार ने सीमावर्ती भारतीय भूमि के प्रति जिस प्रकार का गंभीर, आक्रामक व हठी आचरण अपना रखा है चीन को उसकी आशा तो थी किंतु उसे मोदी सरकार से इस कोरोना कालखंड मे इतनी बलशाली प्रतिक्रिया की आशा संभवतः कम ही थी। चीन का अपने कदम वापिस लेना प्रदर्शित करता है कि वह यह समझ चुका है कि यह नरेंद्र मोदी का भारत है। भारत अपनी सीमाओं के प्रति अपनी चौतन्य व जागृत है व समय आने पर आक्रामक भी हो सकता है यह संदेश चीन को मिल गया है जो स्वाभाविक ही उसे रास नहीं आया है।

वस्तुतः नेपाल ने उत्तराखंड में धारचूला से चीन सीमा पर स्थित लिपुलेख तक रोड लिंक बनाये जाने के विरोध में विपरत स्थित भारतीय राजदूत को समन जारी किया था और भारतीय राजदूत को राजनयिक पत्र सौंपा। नेपाल सरकार का कहना है कि उत्तराखंड में जो सड़क बनायी गयी है, वह उसके क्षेत्र में है। दूसरी तरफभारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हाल ही जिस रोड का उद्घाटन किया गया है वह पूरी तरह से भारत की सीमा में है। इस मार्ग पर आवागमन आसान हो जाने से तीर्थयात्रियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों और व्यापारियों को बहुत सहूलियत मिलेगी। दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान द्वारा एक बांध निर्माण के लिए चीन के साथ समझौता किये जाने पर विरोधप्रदर्शित किया है। नेपाल द्वारा सीमाओं पर हाल ही मे तैनात की गई सेना व नेपाली रक्षामंत्री रक्ष

आत्मनिर्भर भारत का मूल मंत्र गांवों के विकास की गाथा लिखेगा

नरेन्द्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री

यह समय चिंतन का है। वैश्विक महामारी कोविड-19 ने विकास की तस्वीर को बदल दिया है। विश्व की महाशक्तियां आज कोविड-19 से जूझ रही हैं, कई विफल साबित होती नजर आ रही है तो कई देशों की कोरोना नियंत्रण की रणनीति विफल साबित हुई है। ऐसे अवसर पर संपूर्ण विश्व में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अपनी दूरदर्शिता और दृढ़संकल्प शक्ति के बल पर आज राष्ट्र को दुनिया की अग्रिम पांत में लाकर खड़ा कर दिया है। लॉकडाउन को लेकर लिए गए उनके सामयिक निर्णय का ही परिणाम है कि आज घनी आबादी का देश होते हुए भी भारत में कोरोना संक्रमण की दर दूसरे देशों की तुलना में कम है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की चिंता लॉकडाउन की सख्ती से कोरोना की भयावहता को भारत में बढने से रोकने तक ही सीमित नहीं हैं। उनके निर्णयों में लॉकडाउन के परिणामगत देश में उत्पन्न परिस्थियों का समाधान भी परिलक्षित होता है। एक तरफकोरोना की जंग है तो दूसरी ओर लॉकडाउन से उत्पन्न बेरोजगारी के निराकरण के प्रयास। और प्रयास भी इतने पुष्ट की देश आत्मनिर्भरता का बूस्टअप डोज लेकर नवनिर्माण की दिशा में अग्रसर हो।

आत्मनिर्भर भारत का मूल ग्रामीण विकास में छिपा है। यही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कोरोना के बाद उत्पन्न होने वाली वैश्विक परिस्थितियों में भारत को सशक्त बनाने का सबसे बड़ा कदम साबित होगा। कृषि और ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था फिर से भारत की रीढ़ बने। छोटे, मंझोले उद्योगों के माध्यम से एक आत्मनिर्भर सशक्त भारत का निर्माण हो यही संकल्पना है।

अपे गांव लौटे करोड़ों लोगों के रोजगार की चिंता सरकार ने सबसे पहले की है। गांवो में मनरेगा के माध्यम से कार्य करवा कर इसे रोजगार का एक सशक्त माध्यम बनाया जाएगा। मनरेगा योजना के अंतर्गत बजट प्रावधान मे 40000 करोड़ की अभूतपूर्व वृद्धि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की है । मनरेगा का कुल बजट अब 101500 करोड़ रुपए हो गया है। यही नहीं, इस बजट में से 33,300 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी जाकर 23329 करोड़ रूपये की राशि जारी भी की जा चुकी है। देश में अब तक कुल 4.17 करोड़ मनरेगा कामगारों को जॉब आफ्र किया गया है और कुल 20.09 करोड़ से ज्यादा श्रम-दिवस सृजित हो चुके हैं । जब प्रवासी मजदूर अपने गांव पहुंच चुके है तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में प्रतिदिन करीब 2.50 करोड़ मजदूरों को जॉब आफ्र दिया जा रहा है, जबकि

यह संख्या 14 अप्रैल, 2020 को करीब 14 लाख थी । ऐसे में मनरेगा से गांवो में लगभग बीस गुना ज्यादा रोजगार श्रमिकों को मिल रहा है। मई 2019 की तुलना मे 50 प्रतिशत से ज्यादा जॉब ऑफ्र दिये जा रहे है । मनरेगा में 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से औसत मजदूरी में वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में यह 11 प्रतिशत से ज्यादा है।

देश के गांवों के लिए यह एक सुखद संयोग है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय वित्त वर्ष 2020-21 मे 200500 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ग्रामीण भारत के विकाश के लिए खर्च करेगा। इसमें से 51000 करोड़ रुपये राज्यों को जारी किए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री की चिंता में ग्रामीण महिलाएं भी हैं। संकट में उन्हें सशक्त करने के प्रयास किए गए। ग्रामीण प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के पैकेज के रूप में 20.65 करोड़ महिला जन धन खाता धारकों को 500 रुपये की दो किस्त के रूप में 20650 करोड़ रुपये की राशि इनके खाते में अंतरित की गई। वहीं देश में महिला स्व सहायता समूहों के लिए 10 लाख रुपये से निरूशुल्क ऋण की राशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया। यह राशि महिला सशक्तिकरण का आधार बनेगी। 3 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए, दो समान किस्तों में 1000 रुपये की अनुग्रह राशि के भुगतान की घोषणा की गई थी। 2.82 करोड़ लाभार्थियों के लिए 500 रुपये की दो किश्ते जारी की गई। इसके लिए 2805 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थितियों से निपटने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के महिलाओ का भी अभूतपूर्व योगदान मिल रहा है। मिशन से जुड़ी बहने अब तक 12.81 करोड़ मास्क, 3.36 लाख लीटर सैनिटाइजर और 90000 लीटर लिक्विड हैण्डवाश का निर्माण कर चुकी है। मिशन की बहने 12511 सामुदायिक रसोई का संचालन करते करीब 9 करोड़ लोगों के लिए भोजन उपलब्ध करा चुकी है।

कोरोना संकट भी प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास के काम को नहीं रोक सकेगा। हर गरीब को छत मिले इसके लिए प्रयास जारी हैं। आवास के लिए राज्यों के पास कुल 12 हजार 482 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है । प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 2.21 करोड़ आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं, जिसमें करीब 1 करोड़ 2 लाख 51 हजार आवास पूरे किए जा चुके हैं। करीब 48 लाख आवास ऐसे हैं जिनके लिए तीसरी/चौथी किस्त जारी की जा चुकी है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-3 के अंतर्गत 1 लाख 25 हजार किलोमीटर में से 13,900 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत की जा चुकी हैं । करीब 17 हजार किलोमीटर और सड़कों की स्वीकृति का प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन है, जिसे अगले एक महीने में स्वीकृत किया जाना है। ग्रामीण विकास की नींव रख दी गई है। आधारभूत ढांचे में परिवर्तन के साथ ही गांवों में उद्योग और रोजगार के नवअवसर सृजित करके हम गांवों की सशक्तता के लिए जुट गए हैं। कोरोना संक्रमण के बाद बदली हुई दुनिया के स्वरूप में यह भी तय करना होगा कि हमे घनी बस्तियों से अटे पड़े शहर चाहिए या गांव और शहर के बीच का संतुलित विकास। कोरोना ने एक बार फिर इस विषय पर सोचने को दुनिया को विवश कर दिया है। प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता से ग्रामों का विकास नव भारत की नई गाथा लिखेगा।

आतंकवाद नियंत्रण में मीडिया की भूमिका

राजेंद्र मोहन शर्मा, रिटायर्ड डीआईजी

आतंकवाद से जूझ रही दुनिया के सामने आज जिस तरह की उदासीनता व लाचारगी दिखाई दे रही है, वैसी शायद कभी भी नहीं देखी गई होगी। मीडिया के सामने यह बहुत बड़ा प्रश्न है कि आतंकवाद की घटनाओं की किस तरह से प्रस्तुति की जाए क्योंकि कई ऐसी प्रस्तुतियों को मीडिया के सिर थोप दिया जाता है जिसके लिए वह वास्तव में जिम्मेदार नहीं होता। आज भारत में आतंकवाद कई रूपों में अपना फन फैलाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ पाक प्रायोजित आतंकवाद है तो वहीं दूसरी तरफवैश्विक इस्लामी आतंकवाद है जिसे अलकायदा, हिजबुल मुजाहिदीन व तालीबान जैसे संगठन पोषित कर रहे हैं। इसी तरह पूर्वोत्तर व छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में चल रहा नक्सल आतंक है जिसने बाहरी खाल कुछ भी पहन रखी हो, मगर वे भारतीय लोकतंत्र के विरोधी ही हैं। जब आतंकवाद का खतरा इतने रूपों में हो तो मीडिया की उलझनें इसलिए बढ़ जाती हैं कि वह इसे किस रूप में प्रस्तुत करे। एक तरफ आतंकवाद के समाधान की दिशा में सामाजिक दबाव बनाने की चुनौती सामने होती है, दूसरी ओर इस बात का ध्यान भी रखना पड़ता है कि कहीं उसके प्रयासों के थोड़े से भी विचलन से उसे भारतीय लोकतंत्र का विरोधी न मान लिया जाए। यह बात भी सही है कि कई बार मीडिया ने आतंकवाद की फूहड़ प्रस्तुतियां दी हैं जिससे किसी विशेष समुदाय को प्रसन्न करने की कोशिश की गई तथा आरोप-प्रत्यारोप द्वारा अनावश्यक कीचड़ उछाल कर पत्रकारिता की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई। परंतु स्वाभाविक है कि समाज के नैतिक पतन के इस दौर में मीडिया भी यहां इतना शिवम्-सुंदरम् कहां रह गया है तथा मानवीय मूल्यों के हनन में सृजन और संतुलन करने वाला पत्रकार-समुदाय भी अंदर से खोखला, कुटिल, भीरू, कायर, लालची और भ्रष्ट महसूस होने लगता है। परंतु यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हर संकट के समय में भारतीय मीडिया ने अपने देश का गौरव ऊंचा किया है तथा आतंकवाद के विरुद्ध अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की है।

यह भी ठीक है कि जब कोई आतंकवादी घटना घटती है तो मीडिया के विभिन्न चौनलों में खबरों को प्रस्तुत करते की होड़ सी लग जाती है तथा कई बार घटनाओं को सनसनीखेज बना दिया जाता है व कई बार देश में दंगे भी फैलने शुरू हो जाते हैं। आतंकवादी तो अपना प्रचार चाहते हैं तथा इसके लिए मीडिया उनका एक माध्यम बन जाता है। कई बार तो मीडिया को वे अपनी मर्जी से प्रसारण के लिए मजबूर भी करते रहते हैं तथा यदि कोई मीडिया तटस्थ होकर उनकी नंगी तस्वीर का प्रसारण कराता है तो उन्हें मारने की धमकियां आनी शुरू हो जाती हैं। वे एक भय की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हत्याएं चाहे कम हों, मगर उनका प्रभाव अधिक हो। जब मीडिया उनकी घटनाओं को उनके मनमाने ढंग से प्रकाशित करना आरंभ कर देता है तो आतंकवाद अधिक फैलता है।

पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुत से ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने अपना नाम हमेशा के लिए ऊंचा किया है तथा बाकी पत्रकारों को भी उनके नक्शेकदम पर चलने के लिए प्रेरित किया है। उदाहरण के तौर पर पंजाब केसरी के संपादक आदरणीय अमर शहीद लाला जगतनारायण व उनके सुपुत्र रमेश चंद्र जी ने अपनी लेखनी को झुकने नहीं दिया, भले ही उनको अपने जीवन की आहुति देनी पड़ी। समाज को ऐसे देशभक्त पत्रकारों पर नाज है तथा उनका नाम सदा ही सुनहरी अक्षरों में लिखा जाता रहेगा। इसी तरह हाल ही में जीटीवी के मुख्य संपादक श्री सुधीर चौधरी को भी आतंकवादी संगठनों से धमकियां इसलिए मिलनी शुरू हुई हैं, क्योंकि उन्होंने कश्मीर व पीओके की वस्तुस्थिति के बारे में उचित रूप से प्रसारण किया। यही नहीं, हमारे ही देश के कुछ नागरिकों ने उनके विरुद्ध केरल राज्य में 295 आईपीसी के अंतर्गत मामला भी दर्ज करवा दिया। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि देश का हर सभ्य नागरिक ऐसे 'कलम के वीर योद्धाओं' के समर्थन में आगे आए तथा देश में पनप रहे आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करे। मीडिया के लोगों को भी स्वयं अपनी आचार संहिता तैयार करनी चाहिए जिससे उनके प्रसारण द्वारा आतंकवादियों के हितों या लक्ष्यों की प्राप्ति न हो सके।

जिस तरह से सैनिक (सर्जिकल स्ट्राइक द्वारा) दुश्मनों के अड्डों को तबाह करते हैं, वैसे ही कलम के वीर सिपाही आतंकियों का काला चेहरा समाज के सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। वर्ष 1999 में हवाई जहाज के अपहरण के समय मीडिया ने अपनी महत्तवपूर्ण भूमिका निभाकर सभी अपहृत किए गए यात्रियों को छुड़वाया था। इसी तरह देश में जब भी कहीं आतंकी घटना घटती है, मीडिया के लोग अपनी जान हथेली पर रखकर घटनास्थल पर पहुंच कर वहां के मंजर का पूरा विवरण हम तक पहुंचाते हैं तथा हमें ऐसी आसुरी शक्तियों के बारे में अवगत कराते रहते हैं। यह भी देखा गया है कि जब मीडिया में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने लगता है, तब मीडिया के लोग किसी राजनीतिक दल विशेष का भोंपू बन कर अपनी विश्वसनीयता खो बैठते हैं। आतंकवाद पूरे राष्ट्र की समस्या है जिससे निपटने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होने की आवश्यकता होती है, मगर देखा गया है कि राजनीतिज्ञ इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने से बाज नहीं आते। ऐसे में यदि कोई मीडिया अपना सही दायित्व न निभाए तो उस समय उत्तम आदर्श व उज्ज्वल राह दिखाने वाले पत्रकारों पर भी चंद्रमा की तरह कलंक लग जाता है। समाज की रगों में नवचेतना का संचार करने वाले मीडिया समुदाय का विशेष कर्तव्य बनता है कि ज्ञान के आलोक में अपने हाथों में सही हुई लेखनी लेकर तथा भावों और विचारों का अविरल सत्य प्रवाह कर, अनुभूतिपूर्ण एवं अनुभवगम्य सामान्य प्रकाशन ही न करे, अपितु चिरंतन मनीषी बन समाज कल्याण की पवित्र अभिलाषा के प्रति कटिबद्ध होकर एक दक्ष संगठन के रूप में हर संकट का धैर्य से मुकाबला करने में प्रेरित होकर सक्रिय, निष्पक्ष, पुलकित, लिप्साहीन, स्वस्थ आदर्श वाले लौह-संकल्प देकर समाज की अमोघ रक्षापंक्ति बनाने में उद्बेखनीय योगदान दे, ताकि 'सर्वेभवंतु सुखिनः' वाली वैदिक उक्ति अक्षरशः चरितार्थ हो सके।

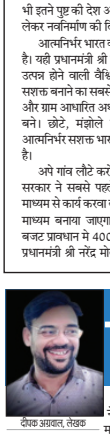

दीपक अग्रवाल, लेखक

कोरोना पर देशी-विदेशी नजरिया

एक छोटे से विषाणु ने पूरे विश्व में कोहराम मचा रखा है,इस अदृश्य शत्रु के खौफसे विश्व के अनेक देश तालाबंदी की गिरफ्त में हैं। डब्लू एच ओ ने कोरोना को सबसे बड़ी वैश्विक महामारी का तमगा दिया है। इस अदृश्य विषाणु का खात्मा करने के लिए विश्व भर के देश युद्ध स्तर पर रात-दिन वैक्सीन खोजने में लगे हैं,लेकिन सफलता अभी दूर है? विश्व के सैन्य शक्ति,परमाणु शक्ति,आधुनिक तकनीक, हथियारों व मिसाइलों से लैस शक्तिशाली देश इस विषाणु के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हैं। कोरोना का कहर मानव जाति पर पहाड़ बनकर टूटा है,जिसके कहर से लाखों की संख्या में लोग संक्रमित होकर जान गंवा चुके हैं। अमेरिका व कई देश कोरोना का जनक चीन को बता रहे हैं,जिसने अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए इस विषाणु को तैयार किया है। इस कारण विश्व भर के देशो में लगभग 2 माह से तालाबंदी है और कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। अब बात करते हैं भारत, अमेरिका, जर्मनी देशों में हुई तालाबंदी की। अमेरिकी नागरिकों को तालाबंदी मान्य नहीं है,उसका पालन न करने पर होने वाले खतरे से भी वे पूरी तरह वाकिफ है। लेकिन अमेरिकियों का मानना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आँच आए बिना कोरोना पर नियंत्रण करें। अमेरिकी टी.वी.चौनलों, अखबार, साक्षात्काराें में नागरिकों की यही मांग रहती है कि जल्द से जल्द तालाबंदी खत्म हो और वे पुनः अपने काम पर लौटे। अमेरिकियों का मानना है कि चीन ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था नष्ट करने के लिए यह विषाणु तैयार किया है,वे इसे विदेशी आक्रमण या युद्ध की तरह लेते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को हर तरह से बचाना आवश्यक मानते है,चाहे उसके लिए जनहानि की कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े? क्योंकि युद्ध में तो जनहानि निश्चित है, इसलिए इसे सहकर भी अर्थव्यवस्था मजबूत करके यह युद्ध जीतना जरूरी है और देश को पुनः पूर्व स्थिति में खड़ा करना है जैसे कोरोना से ठीक पहले था।

जर्मनी से भी लगभग इसी तरह की खबरें मिल रही हैं, जर्मन नागरिक भी तालाबंदी से निजात चाहकर अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर कैसे लाएं? व्यापार को पुनः चालू कैसे करें? भविष्य में इसी तरह के वायरस अटैक हो तो उससे लड़ने के लिए किस तरह की संरचना और सेवा तंत्र बनाया जाए, उत्पादन को कैसे निरंतर चालू रखें ,इस तरह की बातों पर जर्मन नागरिकों के विचार रहते हैं। कई कंपनियाँ अपने कार्यस्थल की संरचना को बदलने की कोशिश में लगी है,कर्मचारियों के बैठने के लिए उचित शारीरिक दूरी के साथ केबिन निर्माण, कार्यस्थल पर सुरक्षा के साथ उत्पादन करने पर काम चल रहा है। मार्केट, मॉल्स आदि स्थानों पर ग्राहकों की सुरक्षा की दृष्टि से हाथों पर सेनेटाइजर ,ऑनलाइन डिलीवरी उत्पादों को सावधानी से ग्राहकों तक पहुँचाने की योजना तैयार करना। इनका एकमात्र विषय देश और देश की अर्थव्यवस्था किस तरह सुदृढ़ बने यही होता है।विशेषतः तालाबंदी की मंदी के समय गृह कार्य जैसे फ़ालतू विषयों पर जोक आदि देखने-सुनने को नहीं मिलते।

इसके विपरीत भारत में क्या हो रहा है तालाबंदी के समय कौन-कौन से मसालेदार व्यंजन बनें, दारू की बातें, मर्दों के खाना- पकाने,कपड़े-धोने,बर्तन-माँजने, पत्नी और उसके मायके के फोन,टिक टॉक पर वीडियो अपलोड,सरकार के बनाए नियमों को तोड़ना, डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मियों पर हमला करना, सरकार को कोसना,नेताओं पर व्यंग्य-जोक आदि से टाइमपास। मजदूरों व कामगारों के अपने घर वापसी की व्यवस्था पर तुच्छ राजनीति करना,किसी भी घटना को बेवजह जाँच के बवंडर में उलझाना, एक तरह एक समाज की स्वस्थ मानसिकता लेकर एक होकर कोरोना से कैसे लडें इस पर कोई पोस्ट,मैसेज नहीं?कोरोना के साथ फिर से कैसे हमारा देश उठ खडा हो बिगड़ती अर्थव्यवस्था कैसे सम्भले इस पर कोई सोच नहीं?कोरोना के बाद देश मे बेरोजगारी जो घर-घर दस्तक देने वाली है उससे कैसे निपटे इसपर कोई चिंतन नहीं?देश,समाज और व्यक्तिगत नुकसान से कैसे उबरे इस पर कोई संदेश नहीं? यदि फिर से कोरोना जैसी महामारी आए तो हमें उससे निपटने के लिए किस तरह तैयार रहना है इस पर कोई विचार नहीं? दोगुनी कीमत में सब्जियाँ अनाज मिले तो उस पर सरकार की ओर से कोई टिप्पणी या कार्यवाही नहीं, दारू के लिए लगने वाली कतार पर ध्यान केंद्रित कर लंबी बहस करना, क्या मानवीय मूल्यों के दृष्टिकोण से हमारा इस तरह का बर्ताव हास्यास्पद महसूस नहीं होता? हम और हमारा देश संकट में है, कोरोना वायरस से मंदी आने वाली है इसलिए मितव्ययी कैसे हो,जरूरी संसाधनों की कैसे बचत करें इस पर कोई अभिमत नहीं?

युवा मन का भटकाव

सुरेन्द्र किशोरी

युवा वर्ग आईना होता है, जिसमें देश का भूत, वर्तमान और भविष्य साफ्सा फ्दिखाई पड़ता है। उनमें हर चुनौती को स्वीकारने का दम होता है। आज भारत को युवा भारत कहा जाता है क्योंकि हमारे देश में असंभव को संभव में बदलने वाले युवाओं की संख्या सर्वाधिक है। आंखों में उम्मीदों के सपने, उमंग और नयी उड़ानें भरता मन, कुछ कर दिखाने का दमखम और दुनिया को मुट्ठी में करने का साहस रखने वाला युवा, देश के भविष्य को तय करता है। लेकिन बदलते दौर में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि युवाशक्ति वरदान है या चुनौती? महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि युवा की शक्ति को सही दिशा में उपयोग नहीं करते तो इनका जरा भी भटकाव इनके भविष्य के साथ-साथ देश के भविष्य को भी दिशाहीन कर सकता है।

संचार क्रांति के प्रसार से जानकारियों की उपलब्धता और भी आसान हुई है। लेकिन यही माध्यम युवाओं में विकृति और भटकाव भी लाया है। आज से दो-तीन दशक पहले हर साधन सुविधाओं से दूर रहकर भी आम युवा धैर्यपूर्वक मेहनत कर अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते थे और सफलता भी पाते थे। आज सुविधाओं से लैस होने के बावजूद अधिकांश युवा सूचना साधनों का दुरुपयोग कर लक्ष्यविहीन हो रहा है। युवाओं की ऊर्जा और जवानी को दिशा देने की जरूरत है। राजनीति में युवाओं की रुचि बढ़ी है और इनकी भागीदारी भी काफ्री महत्वपूर्ण है। शिक्षित युवा, लोगों के अधिकार के लिए कार्य कर बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर युवा आज एक राजनीतिक साजिश के शिकार हैं, जहां उन्हें धर्म, लिंग, जाति, पार्टी के नाम पर बहलाया जा रहा है और आपस में लड़ाया जा रहा। इंटरनेट का सवांचित उपयोग करने वाली युवा पीढ़ी धीरज खो रही है। ये अपनी पुरानी पीढ़ी के संस्कारों को भूल रही है। सोशल साइट्स पर बड़े-बुजुर्गों से सीख लेने के बजाय उनसे उलझना, जातिवादी टिप्पणी कर सुर्खियां बटोरना, महिलाओं के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग कर गौरवान्वित महसूस करना आम बात हो गई है। यह बहुत चिंतनीय है कि युवा पीढ़ी धैर्य, संस्कार, मर्यादा, महिलाओं का सम्मान भूलकर अपनी समय और शक्ति का दुरुपयोग कर रही है।

सामाजिक कार्यकर्ता रजनीकांत पाठक कहते हैं कि बढ़ता तनाव, बेरोजगारी और आधुनिकता का चलन, युवाओं की उम्मीदों और सपनों को मिटा रहा है। युवाओं को लड़ना है तो शिक्षा, सुविधा और रोजगार के अधिकारों के लिए लड़ें। विरोध करना है तो राजनीतिक पार्टियों के गलत फैसलों का विरोध करें। आवाज उठानी है तो दबे-कुचले वर्ग और महिलाओं के सम्मान में आवाज उठाएं। युवाओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि बदलाव लाने की जिम्मेदारी आप पर है इसलिए आपको धैर्य नहीं खोना है। बड़े बदलाव में कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं और उम्र के एक पड़ाव में हर व्यक्ति की आने वाली पीढ़ी से ही उम्मीद होती है। युवा ही देश की दिशा को तय कर सकते हैं। युवा पीढ़ी समाज में फैली उन बुराईयों से बचे जो देश को कमजोर कर रही है, यर्कीनन देश और समाज का भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब आप अपनी ऊर्जा और जवानी खुद की तरक्की में लगाएंगे। आप बढ़ेंगे तो समाज बढ़ेगा, देश बढ़ेगा।

कोरोना का आर्थिक मूल्य

डॉ. भरत झुनझुनवाला
आर्थिक विश्लेषक

कोरोना संकट का आर्थिक मूल्य हर देश को अदा करना पड़ रहा है, लेकिन इसे अदा करने के तीन अलग-अलग रास्ते हैं। पहला रास्ता ब्राजील का है। उस देश ने निर्णय किया कि वह कोरोना का सामना करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा। जितना संक्रमण होता है उसे होने देगा, जिन लोगों की मृत्यु होती है उन्हें मरने देगा, उस देश को आशा है कि जो लोग संक्रमण से बच जाएंगे उनमें कोरोना का सामना करने की इम्युनिटी विकसित हो जाएगी और अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। इस रास्ते को अपनाकर ब्राजील ने भारी मूल्य अदा किया है। ब्राजील में हर 10 लाख जनसंख्या पर 116 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि भारत एवं चीन में केवल तीन लोगों की। बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु का भी आर्थिक मूल्य होता है। जैसे किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि एक वर्ष अतिरिक्त जीवन जीने के लिए वह कितनी रकम अदा करने को तैयार है, तो उसके जीवन के एक वर्ष के मूल्य का आकलन हो जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु 50 वर्ष है और देश के नागरिकों की औसत आयु 75 वर्ष है तो माना जा सकता है कि उसे 25 वर्ष और जीना है। यदि उसके द्वारा एक वर्ष अतिरिक्त जीने का दो लाख रुपए मूल्य बताया गया तो शेष जीवन का आर्थिक मूल्य 25 वर्ष गुणा दो लाख यानी 50 लाख रुपए हुआ। यदि उनकी आज मृत्यु हो गई तो मृत्यु की आर्थिक कीमत को 50 लाख रुपए माना जा सकता है। मेरे आकलन में इस प्रकार ब्राजील अपनी वार्षिक आय का लगभग छह प्रतिशत मूल्य वर्तमान में ही अदा कर चुका है और यह अभी बढ़ ही रहा है। कोरोना का मूल्य अदा करने का दूसरा रास्ता चीन द्वारा अपनाया गया है। यह है कांटैक्ट ट्रेसिंग का। इस व्यवस्था में हर व्यक्ति जो सड़क पर आता है, उसके लिए अनिवार्य होता है कि उसके पास स्मार्ट फोन हो। वह किसी भी संस्था जैसे विद्यालय या दुकान में प्रवेश करता है तो उसे केंद्रीय कम्प्यूटर से अपने ऐप के माध्यम से सूचीकृति लेनी पड़ती है। वहां पर उसका तापमान देखा जाता है। इस प्रकार केंद्रीय कम्प्यूटर को ज्ञान हो जाता है कि वह नागरिक किस समय कहां पर था।

यदि तापमान देखने पर संकेत मिले कि उस व्यक्ति को कोरोना संक्रमण हुआ हो सकता है तो कम्प्यूटर द्वारा चिन्हित कर लिया जाता है कि वह किन लोगों के संपर्क में आया होगा और उन सभी को तत्काल क्वारंटाइन किया जा सकता है। इस व्यवस्था को कारगर रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी भी संस्थान में प्रवेश करते समय स्वीकृति ले और इसमें तनिक भी गफ्लत न करे। इसके बाद सरकारी व्यवस्था इतनी चुस्त हो जो उस व्यक्ति के संपर्क में आए हुए सभी लोगों को तत्काल संपर्क कर क्वारंटाइन कर सके। इस व्यवस्था को सख्ती से लागू कर चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः चालू कर लिया है। इस व्यवस्था का आर्थिक मूल्य न्यून है, लेकिन इसे लागू करने में प्रशासनिक कुशलता चाहिए। कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन आदि का खर्च तो लगता ही है, साथ-साथ इसमें सरकारी दखल का भी संकट है। सरकार को पता लग जाता है कि देश का हर नागरिक किन लोगों से मिला है और उस सूचना का अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को दबाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यदि डाटा लीक हो गया तो चोर को पता लग सकता है कि आप अपने घर पर किस समय नहीं हैं और वह आपके घर में चोरी कर सकता है। अपने देश की प्रशासनिक व्यवस्था चीन की तरह चुस्त नहीं है। इसलिए इस व्यवस्था को लागू कर हम गहरे संकट में पड़ सकते हैं। अर्थव्यवस्था को खोलने से लोगों का आपसी संपर्क बढ़ेगा और कोरोना का संक्रमण भी बढ़ेगा, लेकिन यदि हम संक्रमित लोगों को चिन्हित करके क्वारंटाइन न कर सके तो परिस्थिति बेकाबू हो जाएगी। इसलिए मैं इस व्यवस्था के पक्ष में नहीं हूं। तीसरा रास्ता सोशल डिस्टेंसिंग का है जिसे न्यूजीलैंड और अपने देश में केरल ने सफ्लतापूर्वक लागू किया है। इसमें नुकसान अधिक नहीं है जैसा कि ब्राजील। अपने देश में जिन राज्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग को सही ढंग से लागू किया, वहां संक्रमण नियंत्रित हो गया और जिन राज्यों ने नहीं लागू किया, वहां संक्रमण बढ़ रहा है। अर्थात यह मध्यम व्यवस्था है, लेकिन हमारे लिए यह एकमात्र विकल्प दिखता है। सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने का पहला उपाय यह है कि अपने देश में जितने भी औद्योगिक संस्थान, विद्यालय और प्राएटी कंस्ट्रक्शन साइटें हैं, उन सभी को खोल दिया जाए, लेकिन शर्त यह लगाई जाए कि जितने भी कर्मी या छात्र हैं, उनको उस संस्थान की चारदीवारी में ही रखा जाए। उनके रहने और भोजन की व्यवस्था भी वहीं की जाए। ऐसा करने से अर्थव्यवस्था को हम तुरंत चालू कर सकते हैं।

यदि किसी स्थान पर संक्रमण पाया गया तो उस स्थान पर जितने कर्मी हैं, उन्हें क्वारंटाइन किया जा सकता है तथा शेष अर्थव्यवस्था चलती रह सकती है। इस व्यवस्था को लागू करने में हमको स्वास्थ्य निरीक्षकों को नियुक्त करना होगा जो कि सुनिश्चित करें कि हर संस्थान के लोग अपनी चारदीवारी के अंदर ही रह रहे हैं। उपाय है कि जिन सरकारी कर्मियों का लॉकडाउन के समय कार्य ढीला है, उन्हें स्वास्थ्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जैसे अपने देश में प्राथमिक स्तर पर 58 लाख सरकारी अध्यापक हैं और माध्यमिक स्तर पर 21 लाख। तमाम खाली बैठे हैं। उन विद्यालयों को बंद किया जा सकता है जिनमें छात्रों की संख्या कम है। इन छात्रों को चालू रहने वाले विद्यालयों में स्थानांतरित किया जा सकता है जहां वे रहें और पढ़ें। इस प्रकार हम इनमें से आधे या 33 लाख अध्यापकों को मुक्त कर सकते हैं और इन्हें उद्योगों आदि में स्वास्थ्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। औद्योगिक संस्थानों को कहा जा सकता है कि वे इन स्वास्थ्य निरीक्षकों का वेतन सरकार को अदा करें। इस प्रकार सरकार पर आर्थिक बोझ भी कम होगा और औद्योगिक संस्थान अपनी आर्थिक गतिविधि को चालू करने के लिए इस मूल्य को सहर्ष अदा करना स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार रेल और बस की संख्याओं को आधा किया जा सकता है और बचे हुए कर्मियों को रेलवे के डिब्बों और बसों में स्वास्थ्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा करने से हम सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावी बना सकेंगे और कोरोना के संकट से हमें निकलने में मदद मिलेगी।

न्यूज ब्रीफ

जेल बंदियों से मुलाकात की प्रतिबंध अवधि बढ़ी

माही की गूंज, खरगोन। कोरोना वायरस बीमारी से बचाव के लिए बंदियों से मुलाकात के प्रतिबंध की अवधि को 30 जून तक बढ़ाया गया है। इस संबंध में जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं के महानिदेशक संजय चौधरी ने सभी जेल अधीक्षकों को पत्र लिखकर सूचित किया है कि जेलों में बंदियों एवं उनके परिजनों में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से बंदियों से मुलाकात पर लगाए गए प्रतिबंध को 30 जून तक बढ़ाया गया है।

16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट निषेध

माही की गूंज, खरगोन। मध्यप्रदेश फिशरीज एक्ट के तहत् मत्स्य प्रजनन काल 16 जून से 15 अगस्त तक प्रदेश के निर्दिष्ट जलों, नदियों और जलाशयों पर मत्स्याखेट निषेध रहेगा। मछली पालन विभाग के सचिव समर सिंह ने समस्त संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी किया है। उन्होंने जारी पत्र में कहा कि इस एक्ट के अनुसार छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत, जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और निर्दिष्ट जल की श्रेणी में नहीं रखे गए हैं, के लिए यह नियम लागू नहीं होगा।

टीकाकरण होगा शुरू

माही की गूंज, खरगोन। शून्य से 5 वर्ष तक के छूटे हुए बच्चों के लिए फिर से टीकाकरण का कार्य आज बुधवार से प्रारंभ होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रजनी डावर ने बताया कि टीकाकरण का कार्य खरगोन शहर तथा अन्य नगरों में बनाए गए कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर स्थित सभी आंगनवाड़ियों में बुधवार व शुक्रवार को किया जाएगा। जबकि जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन टीकाकरण किया जाएगा। डॉ. अनुपम अत्रे ने बताया कि इस बार शून्य से 5 वर्ष तक के छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह टीकाकरण निमोनिया, पोलियों, गलघोटू, काली खांसी, रोटा वायरस, हेपेटाईटीस-बी, टीटनेस और मिजल्स रूबैला जैसी कई बीमारियों से बच्चों की रक्षा करेगा। कोरोना वायरस के इस दौर में सभी माता-पिता आंगनवाड़ियों पर बच्चों को लाने से पहले फेस मास्क लगाकर दो गज की दूरी का अवश्य पालन करें। बच्चों के लिए यह दूरी और फेस मास्क किसी टीके या दवाई से कम नहीं है।

पूर्व मंत्री ने स्वेच्छानुदान मद से 29 लाख रुपए किए स्वीकृत

माही की गूंज, खरगोन। पूर्व मंत्री और महेश्वर विधायक डॉ विजयलक्ष्मी साधौ ने वर्ष 2019-20 की तत्कालीन मंत्री स्वेच्छानुदान, विधायक स्वेच्छानुदान व जनसंपर्क निधि से 29 लाख रुपए की राशि स्वीकृति की है। इनमें डॉ. साधौ द्वारा मंत्री स्वेच्छानुदान मद से 12 लाख, विधायक स्वेच्छानुदान मद से 15 लाख एवं जनसंपर्क निधि से 2 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इससे क्षेत्र के करीब 351 विभिन्न हितग्राहियों को लाभ मिला है। इसमें आर्थिक सहायता, बीमारियों के उपचार, शिक्षा में मदद, भजन मंडलियों को संगीत सामग्री, माईक सेट इत्यादि के लिए राशि स्वीकृत की गई है। वहीं इस राशि से लाभांवित हितग्राहियों में सहायता राशि प्राप्त करने वाले शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत वह विद्यार्थी भी शामिल है, जिन्होंने विभिन्न खेलकूद गतिविधियों में भाग लेकर राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन देकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है और बोर्ड परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त किए है। आर्थिक सहायता मिलने पर हितग्राहियों ने डॉ. साधौ को धन्यवाद देकर आभार व्यक्त किया।

प्रारंभ होंगे सभी लोकसेवा केंद्र

माही की गूंज, खरगोन। कोरोना वायरस के चलते भारत सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन के कारण जिले के समस्त लोकसेवा केंद्र भी बंद रहे थे। यह सभी लोकसेवा केंद्र आज गुरूवार से प्रारंभ हो रहे है। लोकसेवा प्रबंधक श्रीमती अर्चना कुंभारे ने बताया कि सभी लोक सेवा केंद्रों पर पहले की तरह सेवाएं प्रदान की जाएगी। सभी केंद्रों पर कोरोना के चलते सभी नागरिकों को फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही सेनिटाईजर की व्यवस्था भी की गई है। सभी लोकसेवा केंद्रों का समय प्रातः 10.30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा।

दुकानें तो खुली लेकिन ग्राहकी नहीं, बाजार खुलने से बाद लोगों के चेहरों पर दिखी रौनक

सराफा दुकानों पर दिखी विशेष व्यवस्था, ग्राहकों ने भी किया नियमों का पालन

माही की गूंज, बड़वाह।

लॉकडाउन-5 में मंगलवार को जिन दुकानों को खोलने की अनुमति मिली है, उनमें से 80 फीसदी दुकानें खुलीं, लेकिन ग्राहकी 2 से 20 फीसदी तक ही हुई। दुकानें खुलने से व्यापारियों से लेकर ग्राहकों के चेहरे खिले हुए नजर आए। बाजार में सुबह व शाम के समय भीड़ होने से अनलॉक के 2 दिन बाद शहर में रौनक दिखाई दी। ग्राहक मास्क लगाकर पहुंचे तो दुकानदारों व कर्मचारियों ने ग्लव्ज तक पहने। दुकानदार खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते नजर आए।

दी एक अनोखी मिसाल

लाकडाउन में मिली छूट के बाद ग्राहक एक बार पुनः बाजार में खरीदी करने को निकला है।वही सराफा व्यापारी कपिल ज्वेलर्स के संचालक अर्पण सराफ ने शासन की गाइडलाईन नियमों के तहत ग्राहकों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए। साथ ही अपनेआप को भी सुरक्षित करने के लिए दुकान में हजारों रुपये की राशि की लागत लागाकर ग्राहक व व्यापारी के आमने सामने कांच की पारदर्शिता लगाई गई। साथ ही ग्राहक को दुकान में सोने, चांदी के आभूषण खरीदने के पूर्व ग्राहक को पूर्ण व्यवस्था के साथ हाथों को सेनेटाइज, ग्लब्स, मास्क, फर्नीचर इत्यादि सुविधा दी जाती है। साथ ही उनके पानी की व्यवस्थाओं के लिए मिनरल पानी की बॉटल भी उपलब्ध कराई जा रही है। ग्राहकों की खरीद दारी करने के बाद चेयर्स को पूरी तरह से सेनेटाइज किया जाता है।

हो रही प्रशंसा

विजय सोनी, सचिन सोनी, लक्ष्मी नारायण सोनी, विजय पगारिया ने बताया कि सराफा व्यापार विगत तीन महीनों में बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तीज-त्योहार, शादी-ब्याह का सीजन पूरी तरह से कोरोना वायरस महामारी से व्यापार चौपट हो गया। वही शासन की गाइड लाइंस को ध्यान में रखते हुए नगर के सराफा बाजार स्थित कपिल ज्वेलर्स के संचालक अर्पण सराफ ने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानियों का ध्यान रखते हुए। दुकान में ग्राहक प्रवेश करते ही सेनेटाइज व चेयर्स को सोशल डिस्टेंसी बनाया रखना अनिवार्य रूप से माक्स ग्लब्स सोने- चांदी के आभूषण को ग्लब्स, पहनकर उठाना, काउंटर को पूरी तरह से सेनेटाइज करने की व्यवस्था कर एक मिसाल कायम की। कपिल ज्वेलर्स की व्यवस्था को देखकर नगर के अधिकांश व्यपारी भी अपनी दुकानों में ग्राहक (कस्टमर) को सुविधा देने के लिए दुकान में व्यवस्था की जा रही है। जो कि नगर में उनकी व्यवस्था को देखकर भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है।

ग्राहकी भी नहीं रही, अधिकांश भाव पूछकर चले गए

कपिल सराफ ने बताया कि सराफा बाजार में मंगलवार को रौनक दिखी। दुकानदारों ने दुकानों से गादियां हटवाकर प्लास्टिक कारपेट बिछवाया ताकि कोरोना का खतरा कम हो। किसी ने सैनिटाइजर की व्यवस्था की तो किसी ने साबुन-पानी की। बाजार बंद होने के समय 21 मार्च को सोना 42500 (10 ग्राम) था जो उछलकर मंगलवार को 48 हजार पर पहुंच गया। चांदी भी पूर्व में 39500 (एक किलो) से जो कि बढ़कर 47 हजार से ऊपर पर पहुंच गई। पूर्व में सराफा दुकानदारों का व्यवसाय 50 से 1 करोड़ के कारोबार वाले सराफा में मंगलवार को व्यापार 15 लाख पार भी नहीं पहुंचा।

निसर्ग तुफान का प्रभाव इंदौर संभाग सहित खरगोन में भी रहेगा

माही की गूंज, खरगोन।

मौसम वैज्ञानिकों द्वारा महाराष्ट्र एवं गुजरात की ओर से टकराने वाले निसर्ग तूफान का प्रभाव मप्र के इंदौर व उज्जैन संभाग में भी रहेगा। इसमें 50 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चलेगी। गरज व चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना, भारी वर्षा की संभावना तथा कहीं-कहीं पर 10-12 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होने की संभावना बताई गई है। अपर कलेक्टर श्री एमएल कनेल ने कहा कि इस संबंध में इंदौर संभागायुक्त श्री आकाश त्रिपाठी ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। पत्र में कहा कि इस आकस्मिक आपदा प्रबंधन के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायत स्तर पर लाउड स्पीकर तथा सोशल मीडिया आदि के माध्यम से मुनादी करवाकर लोगों को सचेत किया जाएं। जिन मंडियों में गेहूं एवं चने की खरीदी चल रही है तथा गेहूं व चना खुले में रखा हो, उन्हें यथाशीघ्र वेयरहाउस में पहुंचाया जाएं।

सेगांव में हुई 3 मिमी वर्षा

पिछले 24 घंटे में जिले की सेगांव में तहसील में 3 मिमी वर्षा दर्ज की गई। भू-अभिलेख कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सेगांव के अलावा जिले की अन्य तहसीलों में बारिश नहीं हुई है। इसके अलावा बुधवार को खरगोन में दोपहर पश्चात रिमझिम बारिश शुरू हुई, जो करीब 3 घंटे तक चली।

परीक्षा केंद्रों को सेनिटाईज करने के दिए निर्देश

माही की गूंज, खरगोन। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 9 जून से हायर सेकेंडरी तथा हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2020 आयोजित होगी। यह परीक्षा जिले के लिए जिले में कुल 90 केंद्र है। इनमें नगरीय क्षेत्र में 27 केंद्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में 63 केंद्र है। इन परीक्षा केंद्रों को सेनिटाईज करने को लेकर कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने सभी नपा सीएमओ एवं जनपद पंचायतों के सीईओ को पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रहे कोरोना वायरस के बचाव के लिए सभी परीक्षा केंद्रों को सेनिटाईज किया जाएं। जिला शिक्षा अधिकारी केके डोंगरे ने बताया कि हायर सेकेंडरी के कुल 17179 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इनमें नगरीय क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों पर 10062 तथा ग्रामीण क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों पर 7117 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र क्रमांक 542017 बाल शिक्षा निकेतन उमावि खरगोन को कोरेनटाईन सेंटर बनाया गया है। इस केंद्र का स्थान परिवर्तन कर अशासकीय संस्था 542028 वैष्णव विद्या मंदिर खरगोन को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। वहीं अन्य जिलों के 480 परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र विकासखंड एवं तहसील स्तर के 12 परीक्षा केंद्रों पर सम्मिलित किया गया है।

सेवा निवृत पर किया सम्मान

माही की गूंज, बड़वानी। कलेक्टरेट बड़वानी के सहायक अधीक्षक संतोष सोनी के 31 मई रविवार को सेवा निवृत होने पर कलेक्टरेट कार्यालय में पदस्थ कर्मियों ने उनके घर पहुंचकर शाल - श्रीफल देकर सम्मानित किया। इस दौरान सभी ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुये अपने मुंह पर मास्क भी लगा रखा था। सोनी के घर पहुंचकर सम्मान करने वालो में कलेक्टरेट अधीक्षक रमेशचन्द्र जोशी, जिला नाजिर निरज अवस्थी, कलेक्टर रीडर मनोज गुप्ता, स्थापना के विजय चौहान, लेखा शाखा के साबिर हुसैन एलची सम्मिलित थे।

प्रतिदिन साढ़े चार हजार से अधिक कार्यो में मिल रहा है 51 हजार से अधिक मजदूरो को रोजगार - सांसद श्री गजेन्द्रसिंह पटेल

माही की गूंज, बड़वानी।

क्षेत्रीय सांसद गजेन्द्रसिंह पटेल ने बताया कि लॉक डाउन के कारण जिले में लौटे प्रवासी मजदूरो को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये वर्तमान में प्रतिदिन 4 हजार 450 कार्यो का संचालन कर 51 हजार 934 लोगो को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं 4 हजार 377 और कार्यो का मस्टर जारी करवाकर रखा गया है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर संबंधित जनपद पंचायत सीईओ तत्काल इन कार्यो को प्रारंभ करवा सके ।

पटेल ने बताया कि बड़वानी के इतिहास में पहली बार एक साथ इतने अधिक कार्यो का संचालन करवाया जा रहा है। जिसके कारण जिले की 416 ग्राम पंचायतो में से 406 ग्राम पंचायतो में संचालित इन 4 हजार 450 कार्यो में 14 आंगनवाड़ी, 2869 आवास, 26 कन्टूर ट्रेंच, 364 कपीलधारा कूप, 198 खेत तालाब, 3 खेल मैदान, 22 गैबियन, 1 घाट कटिंग, 11 चेक डेम, 1 चारागाह, 4 तालाब जीर्णोद्वार, 6 नाडेब, 8 नाला गहरीकरण, 52 निर्मलनीर, 8 निस्तार तालाब, 2 पुलिया निर्माण, 85 बोल्डर चेक डेम, 506 मेढ बंधान, 3 राजीव गांधी सेवा केन्द्र, 43 वृक्षारोपण, 1 शांति धाम, 30 सीसी रोड़, 187 सीसीटी एवं 6 सुदृर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है।

उन्होने बताया कि वर्तमान में जनपद पंचायत बड़वानी में 337 कार्य पर 5152 मजदूर, निवाली में 274 कार्य पर 3017 मजदूर, पानसेमल में 1231 कार्य पर 4927 मजदूर, पाटी में 537 कार्य पर 21863 मजदूर, राजपुर में 750 कार्य पर 5153 मजदूर, सेंधवा में 1046 कार्य पर 8031 मजदूर, ठीकरी में 275 कार्य पर 3791 मजदूर प्रतिदिन रोजगार प्राप्त कर रहे है।

मनरेगा के कार्य के दौरान खुदाई में मिली परमार कालीन प्रतिमा

माही की गूंज, खरगोन। जैन तीर्थ स्थल ऊन के नारायण कुंड में मनरेगा योजनांतर्गत चल रहे कार्य की खुदाई के दौरान जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है। पुरातत्व संग्रहालय के अधिकारी सुलतानसिंह ने बताया कि परमार कालीन यह प्रतिमा संभवतः किसी मंदिर की प्रतिमा होगी, जो मंदिरों के आले (ताक) में स्थापित की जाती है। चूंकि ऊन जैन शिक्षा केंद्र का बड़ा केंद्र रहा है। जैन तीर्थंकर की यह प्रतिमा क्षरित प्रतिमा हैं। इस प्रतिमा में परिचायकों का भी अंकन किया गया है। जनपद पंचायत सीईओ राजेंद्र शर्मा ने बताया कि ऊन के नारायण कुंड में मनरेगा के अंतर्गत नाला उपचार कार्यक्रम किया जा रहा था। इस दौरान खुदाई में ढाई से तीन फिट की जैन तीर्थंकर प्रतिमा प्राप्त हुई है। जानकारी मिलते ही उच्च अधिकारियों को बताया गया और पुरातत्व विभाग से भी संपर्क किया गया। अभी यह प्रतिमा जनपद कार्यालय में रखी गई है। मनरेगा के इस कार्य में 120 मजदूरों को लगाया गया है।

खातों में 5 जून से स्थानांतरित होगी राशि

माही की गूंज, खरगोन। कोरोना वायरस के चलते सरकार की ओर से महिला जनधन खातों में अप्रैल माह से तीन महीने तक 500 रूपए देने की घोषणा की गई थी। अप्रैल व मई माह के रूपए ग्राहकों को बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिए गए है। अब माह जून में भी राशि वितरित की जाएगी। इसके लिए सभी बैंकों व कियोस्क सेंटरों पर इसकी शुरूआत 5 जून से होगी।

नीम, गिलोय और तुलसी अर्क मिश्रित कंडो के धुंए से विषाणु की होगी रोकथाम

माही की गूंज, भीकनगांव।

खंडवा जिले के 540 गांव और भीकनगांव तहसील के लगभग एक दर्जन गांव में नीम गिलोय तुलसी और बिल्वपत्र के अर्क को गोमूत्र और गाय के गोबर में मिलाकर कंडे तैयार किए जा रहे हैं। इन कंडों से घरों में 31 मई को सुबह 8रू00 बजे अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वाधान में गायत्री यज्ञ किया जाएगा। इसके धूएं से घर के वातावरण को विषाणु रोधी किया जाएगा। तहसील के सोमला गांव की पूर्णिमा पवार ने बताया कि, खंडवा जिले के सिरसूद गांव में गायत्री गौशाला में अब तक 11000 से ज्यादा कंडे बनाए जा चुके हैं। इन कंडो को खरगोन व खंडवा जिलों में दिया जा चुका है। गायत्री परिवार के बृजेश पटेल ने बताया कि, खंडवा जिले के 540 गांव में लगभग 5000 बालिकाएं कंडे बना रही है। गौशाला के अध्यक्ष रामकृष्ण पाटीदार ने बताया कि सिर्फ गोशाला में लगभग 30 गाय हैं, जिनके गोबर का उपयोग केवल कंडे बनाने में ही किया जाता है कंडे 72 प्रति नग में दिए हैं ताकि इस राशि से गो आहार की व्यवस्था हो सके। तहसील के रोशिया, लालखेड़ा, मछलगांव, एकतासा, कालाधा, रामपुरा सिराली, नवलपुरा सहित एक दर्जन गांवों में बालिकाएं कंडे बना रही है। यहां कंडे निशुल्क भी वितरित किए जा रहे हैं। नगर के संजीव जोशी ने बताया कि गौशाला से लाकर नगर में दो-दो कंडे वितरित किए जा चुके हैं। खास बात यह है कि, पूर्णिमा पंवार सहित एक दर्जन गांवों में बालिकाओं का समूह नशा मुक्ति व दहेज प्रथा की रोकथाम के लिए भी काम करता है।

रक्तदान शिविर में युवाओ ने किया 50 यूनिट रक्तदान

माही की गूंज, बमनाला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खरगोन बमनाला द्वारा हिन्दू साम्राज्य दिनोत्सव के उपलक्ष्य में सरस्वती शिशु मंदिर बमनाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें बमनाला सहित आसपास के गांवों से आये युवाओं ने रक्तदान किया। समिति के जयगिरि गोस्वामी,उत्कर्ष पांडे व रक्तमित्र प्रखर कर्मा ने बताया की राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा हिन्दू साम्राज्य दिनोत्सव मनाया जा रहा है। वर्तमान में अगर खरगोन जिला चिकित्सालय में ब्लड की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जिसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन हमारे बमनाला मंडल के द्वारा किया गया है। जिसमें करीब 50 यूनिट रक्तदान हुआ साथ ही सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र सौपे गए।

पीएम मोदी देशवासियों को दे रहे आत्मनिर्भर बनने का संदेश -सांसद डामोर

केंद्र सरकार की 1 वर्ष की उपलब्धियां अविस्मरणीय एवं ऐतिहासिक - नायक

माही की गूंज, झाबुआ।

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल के एक वर्ष पूरा होने पर भाजपा शासित केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर स्थानीय सांसद कार्यालय पर बुधवार दोपहर 2 बजे से पत्रकारवार्ता का आयोजन किया गया। जिसमें अतिथि के रूप में सांसद गुमानसिंह डामोर एवं नवीन भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मणसिंह नायक उपस्थित थे। पीसी में सांसद डामोर एवं भाजपा जिलाध्यक्ष नायक ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के एक वर्ष के कार्यकाल को काफी ऐतिहासिक बताते हुए उनके कार्यकाल की भूरी-भूरी प्रसंशा की। साथ ही कहा कि भारत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की मदद करते हुए निरंतर विश्व गुरू बनने की ओर अग्रसर है।

सर्वप्रथम भाजपा जिलाध्यक्ष नायक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के एक साल के कार्यकाल में सबसे बड़े फैसले के रूप में अयोध्या में श्रीराम मंदिर के पक्ष में फैसला, जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटना, तीन तलाक पर रोक, इससे पूर्व के कार्यकाल में जीएसटी लागू कर व्यापार में पारदर्शिता लाना, नोटबंदी के माध्यम से कालाधन की वापसी, पाकिस्तान पर जवाबी सर्जिकल स्ट्राइक, कैप्टन अभिनंदन की वापसी आदि कई बड़े कार्य हुए। कोरोना वायरस (कोविड-19) से रोकथाम के क्षेत्र में भी भारत देश कारगर कदम उठा रहा है। इसी तरह मप्र में भी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में कोरोना वायरस से बचाव की जंग में कई ऐतिहासिक कार्य हो रहे है। निश्चित ही हमारा देश और प्रदेश कोरोना से लड़ाई की इस जंग में फतह हासिल कर संपूर्ण भारत की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पूर्व की तरह बनेगी।

बैठक को संबोधित करते हुये सांसद गुमानसिंह डामोर।

हमे आत्मनिर्भर बनना होगा

सांसद डामोर ने बताया कि अमेरिका की आबादी करीब 33-35 है, वहीं भारत की आबादी करीब 130 करोड़ है, कोरोना से अमेरिका में जितनी मृत्यु हुई है, उतनी हमारी आबादी होने के बाद भी उतने यहां संक्रमित मरीज नहीं है। कोरोना के सामने आज दुनिया के शक्तिशाली देशों ने घुटने टेक दिए है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऐसे वैश्विक संकट के बीच भी भारत में इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए हर कारगर कदम उठा रहे है। आज देश के प्रत्येक नागरिक को आत्मनिर्भर बनना होगा। अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझना होगी।

स्वदेशी अपनाकर देश की अर्थ व्यवस्था मजबूत करे

सांसद ने आगे कहा कि हम स्वदेशी अपनाकर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करे। अब जिन वस्तुओं का फिलहाल हमारे भारत देश में मैन्यूफैक्चरिंग नहीं होता था, वह वस्तुएं भी अब यहीं बनेगी। कोरोना महामारी के बीच भी भारत ने अमेरिका और ईटली जैसे देशों को पीपीई किट, मास्क आदि बड़ी तादाद में उपलब्ध करवाए है। अमेरिका को कोरोना वायरस के प्राथमिक उपचार की क्लोरोकवीन दवाई उपलब्ध करवाई। इस तरह से हर मामले में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। कोरोना से लड़ने के लिए अब हमें मजबूत बनना होगा। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा घर, परिवार और समाज भी स्वस्थ होगा।

इनका जरूर करे पालन

सासंद डामोर ने रतलाम-झाबुआ-आलीराजपुर क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि लाकडाउन खुलने के बाद भी हम घरों से अनावश्यक रूप से ना निकले, घर में बच्चे और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखे। बाजार निकलते समय मुंह पर मास्क अनिवार्य रुप से पहने, सोशल डिसटेनसिंग अर्थात एक-दूसरे से कम से कम 2 गज की दूरी बनाए। हाथों को लगातार सेनेटाईज करे। किसी भी वस्तु को छूने के बाद साबुन से बार-बार हाथों को धोएं। शासन-प्रशासन के सभी निर्देशों का पूरा पालन करे।

यह रहे उपस्थित

यह पत्रकारवार्ता करीब 1 घंटे चली। इस अवसर पर भाजयुमो जिलाध्यक्ष भानू भूरिया, भाजपा नगर मंडल महामंत्री भूपेश सिंगौड, युवा पार्षद पपीश पानेरी, मनोज अरोड़ा, ललित बंधवार आदि उपस्थित थे।

राजनीति का शिकार हो रहें हैं अतिथि विद्वान

माही की गूंज, झाबुआ।

अतिथि विद्वान वर्षों से राजनीतिक मोहरा का शिकार बनते जा रहें हैं। एक और कांग्रेस चुनाव से पहले अपने वचन पत्र में इनके नियमितीकरण मुदे को जोड़कर सत्ता में 15 साल बाद लौटी थी। वहीं एमपी पीएससी की जाँच का वादा और माँग पूरी नहीं करने के कारण भोपाल में 4 माह तक अतिथि विद्वानों का आंदोलन चलता रहा। विभाग के मंत्री रहते जीतु पटवारी ने 3148 सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी और ग्रंथपाल की दिसंबर माह में नियुक्ति दे दी। जिससे 2100 लोग फॉलेन आउट होकर आज तक घर बैठें है। अतिथि विद्वान आंदोलन ने कमलनाथ सरकार को देश दुनिया में हिलाकर रख दिया था। परिणामस्वरूप मांग नही मानने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अतिथि विद्वानों के लिए सड़क पर उतरने का ऐलान किया था, परन्तु 15 माह 6 दिन में ही इसी मुदे को लेकर सरकार गिर गई।

वहीं बीजेपी ने अतिथि विद्वानों को विधानसभा चुनाव 2018 में तवज्जो नहीं दी तथा 15 वर्ष तक इस व्यवस्था को कालखण्ड पर चलाती रही। जिससे 5200 बुद्धिजीवी लोग और उनके परिवार की हाय का सामना नहीं कर सकी, और किनारें पर मिलद गई। दिसंबर से लगातार सीएम शिवराजसिंह चौहान और उनके खेमे के कई मंत्री भरना स्थल पर हित संरक्षण की प्रबल भावना से आए थे। परंतु 23 मार्च से सरकार बनने से लेकर आज तक लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की तारीखें बदलती रहीं। दूसरी और शिवराज सरकार के 5 मंत्री और विधायक समस्या निराकरण का आश्वासन हर रोज दें रहें है। लेकिन पीडा का अन्त नहीं हो सका। शिवराज सरकार द्वारा नजरअंदाज करने का खामियाजा इनके परिजन भी भोग रहें है। इस तरह अपने जीवन और भविष्य का मोहरा दोनों पार्टियों से बनते आ रहें हैं। मोर्चा के संयोजक डॉ. सुरजीत सिंह भदौरिया और मीडिया प्रभारी शंकरलाल खरवाडिया का कहना है कि, यदि फॉलेन आउट अतिथि विद्वानों को सेवा में लेने और नियमितीकरण प्रक्रिया पर शिवराज सरकार शीघ्र ध्यान नहीं देती है तो, आगामी विधानसभा उपचुनाव में इसका खामियाजा अवश्य भोगना पड़ेगा।

प्रदेश के सिनेमा घर आगामी आदेश तक बंद रहेंगे

माही की गूंज, झाबुआ। राज्य शासन ने प्रदेश में संचालित सभी सिनेमा घरों को आगामी आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया है। वाणिज्यिक कर विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसमे कहा गया है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश 30 मई के अनुक्रम में सिनेमा घर बंद रखने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत सभी सिनेमा घरों को इसके पहले 31 मई तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे।

शराब पीने के चक्कर में पुलिस जवान हुए लाईन अटैच

माही की गूंज, झाबुआ। जिले की पारा चौकी पर पदस्थ पुलिस जवान प्रेमसिंह व गुलाबसिंह मोरी, पारा क्षेत्र के ग्राम सिलखोदरी में 30 मई की शाम को ग्रामीणों के साथ रोड किनारे बैठक कर शराब पी रहे थे। मामले का किसी ने इनका विडियो बनाकर वायरल कर दिया। विडियों में दोनों पुलिस जवान किसी ट्रेक्टर दुर्घटना के सिलसिले में भांजगड़ी, लेन-देन करने के लिए गांव में गए थे। विडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक विनित जैन ने दोनों जवानों को लाईन अटैच कर अनुविभागीय अधिकारी को जांच सौंप दी है।

श्रीमती मैना लालन का स्वर्गवास

माही की गूंज, झाबुआ। वरिष्ठ समाज सेवी और कार्पोटिव बैंक के रिटायर्ड अधिकारी राजेन्द्र लालन की धर्मपत्नि और यूरेका फोर्ब्स के चेनल हेड श्याम लालन की माताश्री एवं वरिष्ठ समाजसेवी संजय कुमार कांठी की मामी का रविवार को स्वर्गवास हो गया। श्रीमती लालन पिछले कुछ माह से अस्वस्थ थी। स्व. श्रीमती लालन का अंतिम संस्कार गैल मुक्तिधाम पर हुआ। वरिष्ठ अभिभाषक मनोज मेहता, अशोक राठौर, अजय रामावत, सुरेश कांठी, अमित जैन एवं मनोज जैन मनोकामना, योगेन्द्र नाहर, नितिन धम्मानी, श्याम लालन मित्र मण्डल के अहद खान, सचिन बैरागी, एडव्होकेट दिलीप कुशवाह ने श्रद्धाजली दी। अंतिम संस्कार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुऐ सोशल डिस्टेन्स के साथ हुआ।

सांसद ने निःशुल्क दाल वितरण का किया शुभारंभ

माही की गूंज, झाबुआ। कोविड - 19 की महामारी के चलते ग्रामीण मजदुरों तथा गरीब वर्गों को सतत सहायता मिलती रहे इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार द्वारा सेवा भावना के साथ कार्य कर रही है। लॉकडाउन की अवधि में प्रत्येक व्यक्ति की आरोग्यता के साथ उनके परिवारों की भोजनादि व्यवस्था के लिये केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दे रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अब गरीब वर्गों एवं मजदूरों के लिए अप्रेल से मई तक तहन माह की अवधि के लिए 3-3 किलों दाल का मुफ्त वितरण का कार्य झाबुआ जिले में भी प्रारंभ कर दिया गया है। उक्त जानकारी सांसद गुमानसिंह डामोर ने सोमवार को कालीदेवी में ग्रामीण वर्गों को दाल पैकेट के वितरण के अवसर पर कही। सांसद डामोर ने सोमवार को कालीदेवी स्थित उचित मूल्य की दुकान से दाल वितरण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होने बताया कि अंचल के प्रत्येक परिवार को फिलहाल 1-1 किलो दाल का वितरण किया जा रहा है तथा आगामी दिनों में भी 2-2 किलो के मान से दाल का वितरण कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर कालीदेवी सरपंच विवेक पाल, दिनेश अमलियार सरपंच छापरी, धूरिया सरपंच कोकाद, कातिलाल डावर, नीरजपालिवाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

7500 परिवारों ने किया गृहे-गृहे गायत्री यज्ञ

कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए गायत्री परिवार का आध्यात्मिक अभियान रहा सफल

माही की गूंज, झाबुआ।

अखिल विश्व गायत्री परिवार शातिकुंज हरिद्वार के आव्हान पर स्थानीय गायत्री शक्ति पीठ कॉलेज मार्ग झाबुआ के पण्डित घनश्याम बैरागी तथा नलीनी बैरागी के मार्गदर्शन मे सम्पूर्ण जिले में गृहे-गृहे गायत्री यज्ञ का जिले भर में 7500 से अधिक परिवारों द्वारा प्रातः 9 बजे से सायकाल 5 बजे तक आयोजन करके शास्त्रोक्त विधि से अपने-अपने घरों में श्रद्धा, भक्ति तथा समर्पण भावना के साथ विश्व एवं भारत से कोरोना महामारी की मुक्ति के लिए हवन में आहूतियां दी गई । नलिनी बैरागी ने बताया कि पूरे विश्व में 31 मई रविवार को प्रातः 7 बजे से सायंकाल 5 बजे तक 15 करोड परिवारों में पृथक-पृथक रूप से गायत्री यज्ञ किया गया। बैरागी ने बताया कि गृहे-गृहे गायत्री यज्ञ में हर परिवार में पवित्रीकरण मंत्र के बाद चन्दन धारणम, रक्षा सूत्रम, गुरूपूजन, अग्नि स्थापना के साथ भगवत स्मरण करते हुए गायत्री मंत्र ओम् भूर्भुवस्वः तत्सवितुवरेण्यम् के साथ 24-24 आहूतिया यज्ञ सामग्री के साथ दी गई। इसके बाद 'ओम त्रयम्बकम् यजामहे...माहमृत्युंजय महामत्र के साथ 5-5 आहूतिया यज्ञ में अप्रित की गई। इस आयोजन में प्रत्येक परिवार के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ आहूतियां देने का वृहद आयोजन पूरे जिले में इन घरों में पृथक-पृथक एक साथ किया गया।

इसी कड़ी में कोरोना निर्मूलन के लिए शास्त्रोक्त मंत्रों द्वारा तीन तीन आहूतियां दी गई। देव दक्षिणा पूर्णाहूति मत्रोच्चार के साथ संपन्न हुई। तत्पश्चात विराजंन आरती, कर्पूर आरती के बाद शांतिपाठ किया गया। पूरे जिले में अखिल विश्व गायत्री परिवार के आव्हान पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा लघु यज्ञ में आहूतियां देकर कोराना मुक्ति के लिए प्रार्थना आराधना का अभिनव आयोजन किया गया। घनश्याम बैरागी ने बताया कि जिले में शातिकुंज हरिद्वार द्वारा 2500 परिवारों में गृहे-गृहे गायत्री यज्ञ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिस के विरूद्ध इ।।ब्ु आ जिले में ही 7500 से अधिक परिवारों द्वारा यज्ञ में आहूतियां दिए जाने का कीर्तिमान स्थापित किया गया है। उन्होने बताया कि झाबुआ नगर मे ही 2500 परिवारों ने, थांदला मे 1500, खवासा में 500, पेटलावद मे 1500, रानापुर 250 माण्डली नाथू में 100, मेघनगर अंचल में 650 परिवारों द्वारा निधारित समय पर कोराना मुक्ति के लिए आहूतियां देकर कोरोना के निर्मूलन के लिए अनुष्ठान किए गए।

विश्वशांति की कामना हेतु गृहे-गृहे गायत्री यज्ञ संपन्न

माही की गूंज, सारंगी।

शातिकुंज हरिद्वार गुरुदेव के आदेशानुसार राष्ट्र को समर्थ व शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से गृहे-गृहे गायत्री यज्ञ अभियान के अंतर्गत सैकड़ों घरों में मह्ययज्ञ किया गया। इसमें परिवार के सदस्यों ने सर्वे भवंतु सुखिनरू सर्वे संतु निरामया की भावना से यज्ञ में आहुति कर विश्व कल्याण की प्रार्थना की। गायत्री परिवार के रामेश्वर पाटीदार लीलाशंकर पाटीदार ने बताया गृहे गृहे गायत्री यज्ञ अभियान एक विश्वस्तरीय आध्यात्मिक प्रयोग था, जो विश्व स्तर पर लगभग 2 करोड़ घरों में यज्ञ कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। लक्ष्य से अधिक घरों में गायत्री यज्ञ कार्यक्रम हुए। नगर के लोगों ने अपने अपने घर में परिवार सहित यज्ञ में आहुति दी तथा मां गायत्री से पूरे विश्व व नगर में कोरोनावायरस बीमारी खत्म करने का आह्वान किया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गायत्री परिवार के सदस्यों द्वारा विगत एक सप्ताह से घर-घर संपर्क किया गया था। सोशल मीडिया के माध्यम से भी जन-जन तक यह संदेश पहुंचाया गया था।

70 दिन बाद बामनिया स्टेशन पर 2 जून से हुआ अवध एक्सप्रेस का आवागमन शुरू

माही की गूंज, बामनिया।

कोरोना महामारी संक्रमण के शुरुआती दौर में लगे लॉक डाउन से पहले जनता कफर्यू के दिन 22 मार्च से पूरे देश मे बंद पड़ी ट्रेनों को लगभग आज दो माह से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। जिसके बाद रेलवे द्वारा पहले चरण में 12 मई से 15 सुपरफास्ट कम स्टापेज वाली ट्रेनें चलाई गई थी। जिसके बाद रेलवे द्वारा दूसरे चरण में 1 जून से 200 ट्रेनों को कोरोना वायरस के चलते जारी दिशानिर्देशों के अनुसार शुरूआत की गई। जिसमें बामनिया रेलवे स्टेशन पर भी एक मात्र ट्रेन 19037 अवध एक्सप्रेस का 70 दिन बाद सुचारू रुप से शुरुआत हुई, जो 1 जून को बांद्रा टर्मिनल से शुरू हो कर 2 जून सुबह अपने निर्धारित समय 8रू47 मिनट पर बामनिया स्टेशन पर पहुंची। यह मुजफ्फरपुर की ओर जाएगी। जिसमे दो यात्रियों ने हनीफकुरैशी, नाशिम बानो ने बामनिया से भवानीमंडी की यात्रा करने के लिए चढ़े। वही बांद्रा टर्मिनल से बामनिया की यात्रा कर लालसिंग ओसारी व कामेरी बाई ओसारी बामनिया उतरे। जिनकी स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर मनीष सोलंकी द्वारा थर्मल स्केनिंग की गई। इस ट्रेन के प्रारंभ होने से बामनिया सहित आसपास के क्षेत्र के यात्रियों के लिए काफी सुविधा जनक साबित होगी

यात्रा करने के दिशा-निर्देश व सुरक्षा

कोरोनो संक्रमण के चलते लगे हुए लॉक डाउन के लॉक डाउन 4 के पूर्ण होने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 1 जून से अनलॉक 1 शरू हुआ जिसमें ट्रेन की यात्रा की सुविधा तो मिली पर सुरक्षा की दृष्टि से कई दिशानिर्देशो का पालन करना भेहद जरूरी है । बामनिया स्टेसन के अधीक्षक जितेंद्र कुमार देवड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेन में यात्रा करने के लिए रेलवे द्वारा जारी किए गए कई दिशा निर्देश है जिसमे सबसे प्रमुख ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री का कन्फर्म टिकिट अनिवार्य चाहे जनरल डिब्बे की यात्रा भी क्यो नही करना हो साथ ट्रेन के निर्धारित समय से लगभग 1 घंटे पहले यात्री स्टेसन पर आना जरूरी होगा। जहाँ बामनिया स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टर मनीष सोलंकी की टीम के द्वारा यात्रियों की थर्मलस्केनिंग की जाएगी और प्रत्येक यात्रा करने वाले यात्री के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप्प होना जरूरी रहेगा एवम ट्रेन में यात्रा करने के कई ऐसे दिशानिर्देश है जो यात्रियों पालन करना होंगे जिनकी जानकारी यात्री को टिकिट के साथ निर्देशो जानकारी मिलेगी साथ ही रेलवे द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से स्टेसन परिसर में आने जाने के अलग अगल रास्ते बनाय गए है।एवम बामनिया स्टेसन पर एक टीटी पप्पू राणा की भी नियुक्ती की गई जो यात्रियों के ट्रेन में बैठने से पहले ही टिकिट भी चेक करेगे और प्लेटफार्म टिकिट भी चेक करेंगे एवम प्लेटफार्म पर भी बिना वहज आवाजाही की मनाई है साथ ही बामनिया स्टेसन के आर पी एफ के चौकी प्रभारी उदयप्रताप सिंह के स्टाफके साथ अतिरिक्त 7 आरपीएफजवानों की नियुक्ति की गई है। साथ ही बामनिया नगर के पुलिस चौकी प्रभारी मोहन सिंह सोलंकी भी अपने समस्त स्टाफके साथ मौजूद थे। जिन्होने स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था का विषय ध्यान रखा गया।

भावसार को जिला प्रभारी मनोनित किया

माही की गूंज, झाबुआ। भाजपा मप्र के प्रांतीय अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा वेचुअल रैली एवं अन्य कार्यक्रमों के लिये प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पूर्व जिलाध्यक्ष दौलत भावसार को भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मणसिंह नायक की अनुशंसा पर जिले का प्रभारी नियुक्त किया है। तत्संबंध में भावसार ने बताया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर एवं भाजपा द्वारा विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबध मे जागरुकता अभियान चलाकर जिलेवासियों को इसकी जानकारी दी जाएगी। भावसार ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा उनके 1 वर्ष मे कई ऐतिहासिक निर्णय लेकर देश की एकता अखंडता एवं प्रभुता को मजबुती प्रदान की है। वहीं देश के अंतिम पंक्ति के नागरिको के लिये कई जनकल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की है जिसकी जानकारी भी इस समिति के माध्यम से जिलेवासियों को दी जाएगी। पूरे जिले मे समाज के विभिन्न श्रेणीयों के प्रभावी व्यक्तियो को जोड़कर 100 सदस्यीय समिति बनाकर प्रदेश के निर्देशानुसार पुरे जिले मे कार्यक्रमों की रुपरेखा बनाकर बडे व छोटे आयोजन किया जाना है। समिति के गठन को लेकर भावसार ने बताया कि जिले के डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, उद्योगपति, व्यापारी, छोटे कारोबारी, रेहडीवाले, बिल्डर्स, किसान, महिला संगठन प्रमुख, कर्मचारी संगठन प्रमुख, श्रमिक, प्रवासी मजदुर, स्व-सहायता समुह, स्वयं सेवी संगठन, शिक्षाविद्, वकील उक्त श्रेणीयों के प्रभावी व्यक्तियों को जोड़कर समिति बनाकर वे भोपाल अग्रसित करेंगे। उक्त जानकारी भाजपा मिडिया राजेन्द्र सोनी द्वारा हमारे प्रतिनिधि को दी गई।

कुएं में तैरते हुआ मिला युवक का शव

माही की गूंज, झाबुआ। रविवार को कल्याणपुरा क्षेत्र के पास के ग्राम मुण्डत में एक युवक का कुएं में शव मिलने से आसपास के क्षेत्र मे सनसनी सी फैल गई। वही ज्ञात सुत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि युवक गौरसिंह पिता बिजिया उम्र 25 वर्ष निवासी मुण्डत वह अपने घर से बाजार जाने का बोल के निकला था। लेकिन कई घंटे हो जाने के बाद जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजन परेशान होने लगे। इस पर से परिजनों के द्वारा युवक की तलाश की गई। वहीं कुए के पास से गुजरने वाले कुछ ग्रामीणों के द्वारा कुएं में पड़े शव के बारे में गांव एवं पुलिस में सुचना दी। उसके बाद परिजनों द्वारा देखा गया तो युवक का शव कुए में तैरता हुआ दिखाई दिया। जिस पर से पुरा परिवार सदमे में आ गया। वही मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा कुएं से शव को एक खटिया के जरिये बाहर निकाला गया। वही पोस्टमार्टम कर पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप घटना की जांच में जुट गई है।

कार सवार लोगों ने दिन-दहाड़े की 60 हजार रुपए की लूट, पुलिस कर रही मामले की जांच

माही की गूंज, पेटलावद। बुधवार दोपहर नगर में दिनदहाड़े चोरी की वारदात की घटना को लेकर खबर मिल रही है। किंतु पूरे मामले को लेकर पुलिस की ओर से कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। जानकारी अनुसार नगर के वार्ड क्रमांक 3 में एक शिक्षक नर्मदा-झाबुआ ग्रामीण बैंक से करीब 60 हजार रुपए अपनी सैलरी लेकर निकला था। जिसने वह रुपए अपनी बाइक की डिक्की में रखे थे, जब घर पहुंचा और पीछे-पीछे घर के बाहर कुछ लोग कार से आए और बैंक का पता पूछने लगे और पीछे से एक व्यक्ति ने डिक्की में से रुपए निकाल लिए। इसके बाद वहां से रफूचक्कर हो गए, किंतु वार्ड वासियों की सतर्कता के चलते कार सवारों को पकड़ने का प्रयास किया गया। जिसमें कार का एक व्यक्ति लोगों की पकड़ में आ गया। जिसे पुलिस थाना पेटलावद पर लाया गया है। जहां पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी इस प्रकार बैंक के बाहर घात रख कर चोरी करने की घटना नगर हो चुकी हैं। यदि पुलिस पुराने मामलों को एक बार फिर खंगाले तो पहले की घटनाएं ट्रेस हो सकती हैं।

गेल कम्प्रेशर के पीछे मिला युवक का शव, पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला

माही की गूंज, झाबुआ। मंगलवार को करीब 1.30 बजे गेलर स्थित गेल कम्प्रेशर के पीछे एक शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पुलिस को तिरेज पिता काजली भूरिया निवासी नेगडिया का शव पड़ा मिला। मृतक के शरीर पर कुल्हाड़ी से मारने के निशान पाए गए। पुलिस को पूछताछ के दौरान पता चला कि नेगडिया के ही रालु भूरिया बीती रात 9 बजे तिरेज को लेकर निकला था। लेकिन तब से वह घर पर नहीं लौटा था तथा मंगलवार को दोपहर गेल कम्प्रेशर के पीछे उसका शव मिलने की सूचना मृतक के रिश्तेदारों को दी गई। टीआई कोतवाल सुरेन्द्रसिंह ने बताया कि पुलिस ने संदेह के आधार पर रालु की खोजबीन शुरू कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

दो कुल की तारणहार होती है लड़कियां, पर कलयुगी उर्वशी ने अपने कुल के साथ भारतीय संस्कृति को भी किया कलंकित

लड़के के परिवार उक्त रिश्ते को मान्यता देकर समाज व भारतीय संस्कृति से भी अपने आप को मान रहे बड़ा

माही की गूंज, संजय भटेवरा।

हमारी भारतीय संस्कृति में कहा है कि, लड़की दो कुल की तारणहार होती है। भारतीय संस्कृति की मान्यता अनुसार हमारा समाज लड़की को पराया धन मानते हैं और लड़की के विवाह योग्य होने पर भारतीय संस्कृति एवं परंपरा अनुसार सामाजिक दृष्टिकोण से समाज के ही दूसरे कुल में माता-पिता कन्यादान कर उसका विवाह करवाते हैं और सात फेरों के साथ ही वह लड़की एक कुल से दूसरे कुल में प्रवेश कर दोनों कुल की मान मर्यादाओं को रख अपने दायित्वों के साथ दोनों कुल की तारणहार बनती है। वहीं दूसरी ओर इस कलयुग में कलयुगी लड़की अपने ही कुल की मान-मर्यादा, विश्वास व प्रतिष्ठा को तार-तार कर कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

विश्वास व प्रेम का हनन

आज के युग में बेटियां भी किसी से कम नहीं है कहते हैं और यह सत्य भी है, हमारी संस्कृति सदैव नारी का सम्मान करती आई है और सदैव करती रहेगी। लेकिन जो नारी अपने माता-पिता के विश्वास व प्रेम को तार-तार कर अपने ही कुल को कलंकित करने का प्रयास करें ऐसी नारी को हमारा समाज व संस्कृति कभी सम्मान नहीं देती है। एक माता-पिता बेटों से अधिक अपनी बेटी पर अपना प्रेम न्योछावर करते हैं और अपनी बेटी को सशक्त बनाने हेतु पारिवारिक एवं सामाजिक संस्कारों के साथ वर्तमान परिदृश्य में लड़कियों को उच्च शिक्षा भी प्रदान करवाते हैं। उच्च शिक्षा के साथ माता-पिता अपने संस्कारों के साथ बेटे के साथ बेटी को भी यह जरूर आश्वस्त करते हैं की कभी जीवन में ऐसा कदम मत उठाना जिससे स्वयं को नीचा देखना पड़े और माता-पिता व कुल को शर्मिंदा होना पड़े। तो वही बेटियां भी अपने माता-पिता को आश्वस्त कर विश्वास दिला देती है कि, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े और इसी भरोसे एवं विश्वास के साथ बेटे के साथ बेटी को भी उसका मनचाहा काम व शिक्षा ग्रहण करने हेतु आजादी देते हैं। बेटों के साथ बेटियां भी संस्कारों के साथ शिक्षा प्राप्त कर अपने माता-पिता परिवार व क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं जिसकी वाह-वाही चारों और होती है और माता-पिता का सीना भी गर्व से ऊंचा होता है। तो वही येन-केन ऐसे बेटे-बेटी भी होते हैं जो माता-पिता के प्रेम व विश्वास का हनन कर किताबी ज्ञान से अर्जित की गई शिक्षा से अपने आप को सर्वोच्च ज्ञानवान मानकर अपने माता-पिता, परिवार एवं समाज की मान-मर्यादा को धुमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, जिससे माता-पिता ही आहत नहीं होते हैं वरन परिवार व समाज के साथ वह हर माता-पिता आहत होते हैं जो अपने बेटे-बेटी पर भरोसा कर उनकी मान-मर्यादाओं को कलंकित करते हैं। और खासकर ऐसे कुछ मामले देख आज भी हमारे समाज में माता-पिता खासकर बेटियों को ऐसी बेटी जिसने माता-पिता के प्रेम व विश्वास का हनन किया है का उदाहरण देकर उच्च शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है।

कलयुगी युगत जिन्होंने अपनी ही कुल की प्रतिष्ठा को किया धुमिल।

गूंज में दिनांक 30 अप्रेल को 'परिवार के प्रभुत्व की विचारधारा को अमल कर अपने ही परिवार की भुआ को भतिजा लेकर भागा', 'कलयुगी युगल भुआ भतिजे ने गरबा डांस का किया विडीयो वायरल, लडकी के माता-पिता है मानसीक तनाव में' शीर्षक के साथ समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें राणापुर पडियार परिवार के एक ही कुल में जन्मे भुवा-भतीजा भाग गए और लड़की के पिता ने समाज से लड़की को ढूंढने में मदद करने एवं लड़की को सुपुर्द करने की अपील समाज से की थी।

लड़के के पिता व काका ने परिवार, समाज व प्रशासन को भी किया गुमराह

राणापुर स्व. लुणाजी पडियार परिवार का परपोता कमलेश पडियार का पुत्र व किशोर पडियार का भतीजा अपने ही पिता के काका यानी अपने छोटे दादाजी जोबट निवासी निर्भय पडियार की लड़की उर्वशी के साथ भाग गए। लड़की के पिता ने समाज से लड़की को ढूंढने की अपील के साथ लड़के के पिता व काका ने लड़का-लड़की मिलने के बाद समाज के माध्यम से लड़की को उसके माता-पिता को सुपुर्द कर देंगे का विश्वास दिया। लेकिन दो माह बाद 18 मई को पुलिस थाना थांदला में स्वयं के साथ भारतीय संस्कृति को कलंकित करने वाला युगल पेश हुआ। मेवाड़ा कलाल समाज झाबुआ-अलिराजपुर के अध्यक्ष डाडमचंद लोदावरा के अनुसार थाने में लड़का-लड़की के आने के बाद लड़के के काका किशोर ने पुलिस थाने में आने की सूचना दी, जिस पर बड़ी सहजता के साथ समाज के 2 लोगों के साथ थाने पहुंचे की लडकी को समझा कर लडकी के माता-पिता के सुपुर्द कर देंगे, लेकिन थाने पर जाकर देखा कि, कमलेश व किशोर पडियार, उसीके पडियार परिवार के साथ समाज को भी गुमराह कर रहा है, थाने पर उसके चहते व गांव का एक प्रभुत्व के साथ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे और वह लड़की सुपुर्द करने की बजाय ऐसा माहौल बना रहे थे कि, समाज के अध्यक्ष एवं उसके माता-पिता व परिवार विवाद करने को उतारू हो जाए।

अध्यक्ष के अनुसार एक ही परिवार में यह रिश्ता सामाजिक, भारतीय संस्कृति के साथ कानूनन धारा 5 के अंतर्गत वैध नहीं है तो, क्या गांव के प्रभुत्व व जाने-माने जो लोग लड़के पक्ष में थाने पर आकर इस रिश्ते को सही ठहराने का प्रयास कर रहे थे, क्या उस समाज व परिवार के साथ उनके घर में एक ही परिवार की बहन, भुआ या बेटी के साथ विवाह को मान्यता देते है क्या? का जवाब उन समाजजनो से जो इस रिश्ते को मान्यता देकर यहा पहुंचे थे, से जानना चाहा है। तो वही लड़के-लड़की ने अपने आप को बालिक होना बताकर की गई शादी के प्रमाण थाने में पेश किये एवं भुआ-भतीजे के पति-पत्नी के रूप में साथ में रहने का निर्णय लिया।

इस रिश्ते को लड़के के माता-पिता व काका ने स्वीकार कर उन्हें अपने घर ले गए वरन अपनी ही बहन व ननद को बहू के रूप में स्वीकार कर गांव में अपनी ही एक मासी के यहां जाकर पैर छूने की सामाजिक प्रथा का निर्वहन किया। तो वही मासी परिवार इस रिश्ते को मान्यता नहीं देने हेतु घर पर बुलाकर समझाइश देने की बात कर रहा हैं।

लड़की के पिता व समाज के अध्यक्ष के साथ प्रमुत्वजनों द्वारा भारतीय संस्कृति को बचाने का किया प्रयास, तो भी परिजनों ने किया गुमराह

यह सब कुछ होने के बाद भी लड़की के पिता ने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए लड़की अगर आती है तो बेटी के रूप में पुनः स्वीकार करने की बात कही। जिस पर समाज ने पुनः एक बार समाजहित में दायित्व निभाते हुए एक कमेटी के माध्यम से लड़के के पिता एवं काका के साथ लड़के-लड़की से भी संपर्क किया। जिसने भी समाज के प्रभुत्वजनों के अनुसार निष्कर्ष निकलकर आया कि, लड़के के पिता एवं काका ही पूरे मामले में सहयोगी रहे और महंज समाज को गुमराह कर कभी इस रिश्ते को स्वीकार करने की बात तो, कभी लड़की के परिवार ने लज्जित करने की बात कह कर उन्हें नसीहत सिखाने की तर्ज पर कहते हैं, हम अगर चाहते तो 2 मिनट में इसका समाधान कर देते कि, बात भी करते रहें। वही लड़का-लड़की भी कुछ शर्तों के साथ संबंध विच्छेद कर, लड़की पिता के घर जाने के लिए तैयार हूं कहा, दोनो के सभी तर्क मानकर उनके ही तर्क अनुसार समाज के प्रभुत्वजनों ने उसे लड़के-लड़की एवं लड़की के माता-पिता की ओर से लिखित एवं कानूनी प्रक्रिया के साथ इस विवाह को शून्य करने की बात रखी। लेकिन गुमराह करने वाले लड़के-लड़की के साथ इनके सहयोगी पिता एवं काका सभी लड़की के कंधे पर बंदूक रख कलंकित करने वाले रिश्ते को शून्य नहीं करना चाहते है समाजजनो के सामने आया।

इस संबंध में बताया जा रहा है कि, समझाईश के बाद भी नहीं मानते हैं तो लड़की के पिता उनकी पुत्री उर्वशी को पुत्री धर्म से त्याग कर उनकी और से जीते जी क्रिया करने की बात कर रहें हैं। तो वही समाज भी अपने घर एवं परिवार की बहन-बेटी को अपने ही परिवार से सुरक्षित रखने के लिए स्वैच्छिक रूप से लड़के परिवार से सामाजिक रिश्ता नहीं रखने का मन बना चुका है, जिसमें समाज के अध्यक्ष व कुछ प्रभुत्वजनों का तर्क है कि, अगर आज स्वैच्छिक रूप से सामाजिक दूरियां इस परिवार से नहीं बनाई तो तय है इसी का उदाहरण देकर फिर कोई लड़के-लड़की कलाल समाज में ही नहीं वरन हिंदू धर्मावली में कोई सगा भाई-बहन या भुआ-भतीजे ऐसा ना कर सके इसके लिए समाज के हर परिवार को स्वैच्छिक रूप से ऐसा कदम उठाना आवश्यक माना जा रहा है।

तो वहीं इस पूरे मामले में प्रशासन को गुमराह किया या फिर प्रशासन की लापरवाही रही जो भी हो लेकिन उक्त युगल इन्दौर रेड जोन में रहकर लॉकडाउन में राजस्थान व गुजरात जाकर 18 मई को थांदला आए थे, परंतु प्रशासन ने नहीं इनका मेडिकल करवाया नहीं इनको क्वारंटाइन किया। जब भारतीय संस्कृति के साथ कानून भी एक ही परिवार के लड़के-लड़की के विवाह की मान्यता नहीं देता तो, आखिर किस कर्मकांठी पंडित व किस धार्मिक संस्था ने किस आधार पर यह गंधर्व विवाह संपन्न करवाया, इसका खुलासा अगले अंक में

निरंतर...

आम्बापाड़ा बैराज से बाहर के लोग ले रहे पानी, किसानों की भूमि को पहुंचा रहे हैं नुकसान

पीठडी और आम्बापाड़ा के किसानों ने की शिकायत

माही की गूंज, पेटलावद। आज पेटलावद कि क्षेत्र ग्राम आम्बापाड़ा और पीठड़ी के किसानों ने अनुविभागीय अधिकारी के नाम एक शिकायत पत्र तहसीलदार जितेंद्र अलावा को सोपते हुवे बताया बताया कि ग्राम आम्बापाडा में बड़े तालाब जिसे आम्बापाड़ा बैराज भी कहा जाता है उक्त तालाब में गांव के किसानों की भूमि जमीन डूब गई जिससे लाभ यहाँ के किसानों को मिलना था लेकिन ग्राम सेमरोड हवासी जिनके खेत तालाब से बहोत ज्यादा दूर ओर तालाब के कमांड क्षेत्र में भी नही आते बिना सक्षम अधिकारी से बिना अनुमति लिए हमारे खेतो से बलपूर्वक खुदाई का कार्य करते थे और हमारी खेती को नुकसान पहुचा जा रहा है और जब इनको रोका गया तो जान से मारने की धमकी दी जा रही है । किसानों का आरोप है बहारी किसान तालाब से पानी लेने ओर पाइप लाइन के खेत को नुकसानी ऐसे ही पहुचाते रहे तो हमको आंदोलन पर मजबूर होना पड़ेगा , मामले में जल संसाधन विभाग के एसडीओ का कहना है कि किसानों की शिकायत मिली हैं

लेकिन हमने केवल कमांड क्षेत्र किसानों को तालाब से पानी उठाने की अनुमति दी है पाइप लाइन बिछाने की नही दी यदि किसानो की निजी भूमि से लाइन जा रही है तो किसान उनको रोक सकते हैं या लाइन ले जाने की अनुमति दे सकते हैं।

विवादित भूमि पर की चने की उपज और गेहूं उपज का फर्जी पंजीयन करवाकर संस्था में तुलवा दिए गेहूं

माही की गूंज, खवासा।

आमलोगों के हक का पैसा सरकारी खजाने से किस नए नीत तरीके से निकाला जाता है यह पता ही नहीं चलता, जिसका एक उदाहरण सामने आया है।

कृषि का धंधा लाभ का धंधा बने इसलिए किसानों का मनोबल बढ़ाने हेतु उपज की गई फसल का बोनस के साथ खरीदी केंद्र पर सरकार खरीदी करती है, परंतु यहां भी व्यवसाय करने वाले एवं माफिया अपनी कारस्तानी दिखाकर कई किसानों के नाम पर जिस फसल की उपज किसान करता ही नहीं, उसका पंजीयन करवाकर बाजार का वह अनाज किसान के नाम से तुलवा दिया जाता है। ऐसे कई मामले सामने आए भी है परंतु फिर भी इस पर कोई नकेल नहीं कसी जाती है, नतीजन आमजन का पैसा सरकारी खजाने से किसानों के नाम पर फर्जी रूप से अनाज तुलवाकर राशि आहरण कर ली जाती है।

वही खवासा आदिम जाति सहकारी संस्था में एक ऐसा मामला सामने आया है कि, सन् 1990 से सर्वे खाता नंबर 397, 442, 1538, 1404 जिसके मालिकाना हक को लेकर दो बहनों एवं भानेज के बीच विवादित भूमि होकर मान्य उच्च न्यायालय तक प्रकरण चल रहा है जो आज तक विचाराधिन है, उक्त भूमि पर वर्तमान में सोहनबाई व उनके पति कनीराम जी डेरिया के साथ उनके पुत्र का कब्जा है, न्यायालय में विचाराधीन उक्त मामले में विपक्षी समरथबाई पति हीरालाल पाटीदार निवासी करवड़ के नाम से आधी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण करने के आदेश मान्य उच्च न्यायालय इन्दौर ने दिए, पर उक्त भूमि का हक अभी नहीं दिया जाए के भी आदेश दिए। तो वहीं सोहनबाई एवं कनीराम जी डेरिया के कब्जे की उक्त विवादीत पूरी कृषि भूमि पर चने की फसल की बोवनी कर उपज की थी, परंतु विपक्षी ने वर्तमान में वहां किसान कब्जे की भूमि खाता क्र. 397, 442, 1538ध्2 की कृषि भूमि पर फर्जी रूप से गेहूं की फसल की उपज बताकर खवासा के आ.जा.स. संस्था में फर्जी पंजीयन के साथ ही फर्जी रूप से बाजार का 81 क्विंटल गेहूं 24 मई को तुलवा दिया जिसका पैसा भी 2 जून को 1 लाख 55 हजार 925 रूपए सीसीबी शाखा बामनिया में विपक्षी श्रीमति समरथबाई पाटीदार के खाते में जमा हो गई हैं। वही कब्जाधारी सोहनबाई के पुत्र नारायण पाटीदार ने मान्य उच्च न्यायालय में विवादित भूमि के चल रहे विचाराधिन प्रकरण एवं विपक्षी के पास जमीन का कब्जा नहीं होने व पूरी भूमि पर चने की फसल की उपज करने के बावजूद विपक्षी के पुत्र ने फर्जी रूप से संस्था में पंजीयन करवाकर बाजार का गेहूं तुलवाने एवं न्यायालय तक को गुमराह करने के आरोप के साथ उक्त तुले गेहूं की जांच करने एवं बैंक खाते से राशि आहरण नहीं करने की पुलिस चौकी, आ.जा.स. संस्था से लेकर कलेक्टर तक जांच करने हेतु शिकायत दर्ज की है।

प्रधानमंत्री आवास की अटकी पड़ी फाइल खिसकी, विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने किया सर्वे

गुमान की राजनीति आड़े नहीं आई तो जल्द होगा पहली किश्त का आंवटन

माही की गूंज, पेटलावद।

पिछले अंक में ष् एक साल 202 परिवार बेहालष् शिर्षक से प्रकाशित समाचार के माध्यम से एक साल से अधिक समय मे पेटलावद के 202 परिवार को मिलने वाला प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अटका हुवा था , पहली किस्त की पूरी राशि नगर परिषद के खाते में 08 माह से जमा हो कर आबंटन नही हो पा रहा था पूरे मामले में सांसद गुमानसिंह डामोर सहित शहरी विकाश प्राधिकरण झाबुआ के अधिकारियों और जिला कलेक्टर की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे थे , पूरी योजना के लाभ के लिए नगर परिषद ओर हितग्राहियों के बीच जिले की राजनीति, वर्चस्व, दबाव ,प्रभाव और कमीशन की दीवार खड़ी हो गई थी । मामले को गूँज द्वारा प्रमुखता से उठाने के बाद योजना की फाइल आगे बढ़ी है जिसके तहत नगर परिषद द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद आदेशानुसार टीम गठित कर प्रधानमंत्री आवास घटक की शुची एडीएम साहब को 29 मई को भेजी गई जिस पर एडीएम साहब के आदेशानुसार परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास के कमलेश गोले एवं लिपिक रामपुरिया द्वारा नगर परिषद सीएमओ लालसिंह राठौड़ के साथ सोमवार को नगर के आवास हितग्राहियों के घरों का सर्वे किया गया जिससे हितग्राहियों को उम्मीद जगी है कि जल्द ही योजना का लाभ मिलेगा और सपनों का मकान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने के साथ साकार होगा ।

202 में 189 लोगों को मिलेगा लाभ

नगर परिषद के सर्वे के अनुसार नगर के 202 लोगो को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ के लिए सूचिबद्ध किया था किन्तु 08 हितग्राहियों पर आपत्ति के कारण उनके नाम हटा दिए गए थे , सोमवार को हुवे सर्वे में 04 लोगो को हटाया गया जिसमें 02 हितग्राही मकान का निर्माण कार्य योजना के लाभ मिलने को आस में शुरू कर दिया था और मकान बना लिया , जबकि दो हितग्राहियों ने मकान बेच लिया जिससे उनको योजना के लाभ से वंचित किया गया अब 189 लोगो को आवास योजना का लाभ मिलेगा ।

सांसद को भी दिखानी पड़ी रुचि

खबर लगने के केंद्र का जिले में प्रतिनिधित्व कर रहे सांसद गुमानसिंह डामोर को भी मामले में रुचि दिखनी पड़ी , मिली जानकारी के अनुसार मामले में सांसद ने अपने प्रतिनिधि राजेश कासवा को नगर परिषद भेज पूरे मामले की जानकारी ली , जिस तरह से पूरा प्रशासन और सांसद सक्रिय हुवे हैं उससे लोगो को अब लग रहा है योजना से जुड़े लोग स्वहित त्याग कर जनता हित को ध्यान में रख लोगो को लाभ दिया कर अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

नगर परिषद के जिम्मेदारों के साथ हितग्राहियों का सर्वे करते झाबुआ विकास प्राधिकरण के अधिकारी।

तेज आंधी में पेड़ का बड़ा हिस्सा गिरा

माही की गूंज, थांदला। सोमवार को दिन भर तेज तपन और नौतपा से नगरवासी परेशान थे। लॉकडाउन के चलते शाम 4 बजे बाजार में सन्नाटा पसर चुका था। शाम 4 बजे से ही तेज हवाओं से प्री-मानसून की आहट सुनाई देने लगी थी। शाम 6 बजे से तेज हवाओं के साथ ही धूलभरी आंधी के साथ पानी की बौछारें आसमान से होने लगी। तभी नगर के महात्मा गांधी आर्ग स्थित रामेश्वर मंदिर के समीप एक पेड़ की भारी भरकम शाखा टूट कर बीच सड़क पर आ गिरी। अच्छी बात यह रही कि लॉकडाउन के चलते यहां सब्जी बाजार उठ चुका था अन्यथा कोई जनहानि होना संभव थी। वृक्ष की शाखा गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गया और भीड़ जमा होने लगी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422